डाक पंजीयन क्र. L/ RNP/म.प्र./ मन्दसौर/122/ 2024- 26
ई-पेपर www.guruexpress.live

बात आपकी, शब्द हमारे

गुरु एक्सप्रेस

सुबह का अखबार

संपादक – आशुतोष नवाल

वर्ष 19 | अंक 256 | पृष्ठ 4 | मन्दसौर | बुधवार 02 जुलाई 2025 | मूल्य 2 रुपया

हार्ट केयर
श्री सिद्धि विनायक
अब नियमित सेवाएं मंदसौर में उपलब्ध
हृदय रोगों के उपचार में अंचल का जाना पहचाना नाम
हृदय रोग विशेषज्ञ
डॉ. पवन मेहता
MBBS, M.D. (Medicine) I DM (Cardiology)
Consultant Interventional Cardiology
परामर्श समय -
प्रतिदिन प्रातः 10:00 से सायं 5:00 बजे तक
12, दशपुर कुंज रोड, सिविल हॉस्पिटल के सामने, मंदसौर (म. प्र.) 07422-490333

एमपीईबी अधिकारियों को ई अटेंडेंस से राहत

भोपाल, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। विद्युत वितरण कंपनियो में अधिकारियों, कर्मचारियों की अटेंडेंस को लेकर बवाल मचा हुआ है। विभिन्न विभागों ने इसके लिए सख्त प्रावधान किए हैं, अटेंडेंस के लिए एप तक बना दिए गए हैं। हालांकि अधिकारियों, कर्मचारियों ने इनका तगड़ा विरोध भी किया है।

ऐसे माहौल में मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सैल्फी अटेंडेंस को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कंपनी ने अपने मैदानी अधिकारियों के लिए इसमें खासी छूट दी है। फील्ड अधिकारियों को अब दिन में एक बार ही हाजिरी लगानी होगी। कंपनी के मुताबिक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और कार्य आवश्यकताओं के लिए फील्ड अधिकारी अक्सर मैदानी भ्रमण पर रहते हैं। वे रखरखाव, विद्युत आपूर्ति और अधोसंरचना संबंधी कार्यों के लिए ग्राउंड पर आते जाते रहते हैं। जिससे उपस्थिति समय-सारणी का पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में फील्ड कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इन अधिकारियों को उपस्थिति में छूट देने का निर्णय लिया गया है।

अब जेई एवं उससे ऊपर के फील्ड अधिकारियों को दो बार उपस्थिति दर्ज करने के स्थान पर दिन में कार्यालयीन समय में एक बार उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस (ओएंडएम), एसटीएम/एसटीसी/, सतर्कता, बीआई सेल तथा सिविल विभागों में फील्ड ड्यूटी पर तैनात कनिष्ठ अभियंता (जेई) एवं उससे ऊपर के अधिकारियों को 'अटेंडेंस पोर्टल 2.0' पर दो बार सैल्फी उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाएगी। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि फील्ड ड्यूटी पर लगे जेई एवं उससे ऊपर के फील्ड अधिकारी किसी भी सुविधाजनक समय पर केवल एक बार उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे।

हालांकि कॉर्पोरेट कार्यालय में पदस्थ अधिकारी या फील्ड इकाइयों में केवल कार्यालयीन कार्य कर रहे अधिकारी, पूर्ववत दो बार उपस्थिति दर्ज करने की प्रणाली का पालन पूर्ववत: करते रहेंगे। अन्य सभी कर्मचारियों, जिनमें आउटसोर्स कर्मचारी भी शामिल हैं, पर प्रचलित उपस्थिति प्रणाली प्रात: 10:00 बजे तक पंच-इन तथा शाम 6:00 बजे तक पंच-आउट करेंगे। कार्यावधि 08 घंटे की लागू रहेगी। कंपनी ने कहा है कि यह छूट केवल फील्ड गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए है तथा यह सुविधा कार्मिकों के कार्यस्थल पर उपस्थित रहने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती। यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 01 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी।

अभियान की हकीकत बयां करती मरी हुई मछलियां..?

महत्वपूर्ण जलस्त्रोत चीख-चीखकर बता रहे हकीकत, रिजल्ट तालिका पहले ही दिखा चुकी है आईना

मंदसौर, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। जलगंगा संवर्धन अभियान में मंदसौर नीचे से टॉप टेन जिलों में शामिल रहा। इस अभियान मे मंदसौर 50 प्रतिशत भी नहीं ला सका। इधर रिजल्ट ने आईना दिखाया तो जल संवर्धन अभियान के तहत प्रशासनिक दावों की पोल तैलिया तालाब में मछलियों की लाशें खोल रही है। अभियान के प्रदेश स्तरीय रिजल्ट के साथ ही शहर के प्रमुख जलस्त्रोत चीख-चीख कर जिले में अभियान के तहत की गई औपचारिकता की पोल खोल रहे हैं। शिवना हो या तेलिया तालाब या नाहर सैय्यद तालाब मानसून खत्म होते ही एक-एक बूंद के लिए तरसने लगते है। संरक्षण की योजना नगरपालिका, एप्को, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग, जल संसाधन विभाग, पीचएई, पंयायती राज विभाग के अफसरों की पंचायत में ही उलझकर कागजों में दम तोड़ देती हैं।

नपाध्यक्ष के पत्र के बाद भी जहरीला पानी...

कुछ माह पहले तैलिया तालाब के पानी में घूल रहे दूषित और प्रदूषित पानी को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष को कलेक्टर को अवगत कराकर कार्रवाई के लिए पत्र लिखना पड़ा। जबकि, एनजीटी इसको लेकर नगरपालिका को काफी समय पहले निर्देशित कर चुकी है। इधर अभी भी महू-नीमच राजमार्ग पर मंडी से आगे तक बनी लगभग 16 कॉलोनियों एवं फैक्टरियों का गंदा पानी मिल रहा है। प्रोजेक्ट और दावों के बीच सालों निकाल दिए गए। अब तालाब का पानी जहरीला हो गया है। इसका प्रमाण है तालाब में आए दिन हो रही मछलियों की मौत। फिर से तैलिया तालाब के जहरीले पानी में मछलियां दम तोड़ने लगी है।

योजना पर योजना, खर्च पर खर्च...

करीब 20 साल से शिवना को शुद्ध करने के लिए योजना पर योजना लाई जा रही है। करोड़ो रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं। लेकिन, परिणाम जस का तस। जलकुंभी तक जिम्मेदार नहीं हटा पाए है। सिर्फ बारिश के पानी में बहकर शिवना का आंचल जलकुंभी से मुक्त नजर आता है। इसके बाद कहानी वहीं की वहीं।

नाहर सैय्यद तालाब...

नाहर सैय्यद तालाब की तो जिम्मेदारों ने मानों हत्या ही कर दी हो। इसका अस्तित्व ही अब खतरें में है। संवारने की योजनाएं फाईलों में दफन हो चुकी है। तालाब का पानी पीने योग्य तो दूर की बात है, यहां के पानी में नहाया भी नहीं जा सकता। जबकि, एक समय नाहर सैय्यद तालाब कई घरों की प्यास बुझाता था।

बारिश के कारण कई किसानों को करना होगी दोबारा बोवनी

मंदसौर, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। जिले में अब तक करीब 75-80 प्रतिशत बोवनी हो चुकी है। लेकिन, 13 जून से जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में हो रही रिमझिम तो कभी तेज बारिश से बनी नमी ने बोवनी पर ब्रेक लगा दिया है। कई किसानों को अब बारिश में कुछ ढील का इंतजार हैं। कुछ क्षेत्रों में पहली बोवनी बिगड़ने के बाद दूसरी बार बीज लगाने पर मजबूर होना पड़ेगा। इधर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। जिले की औसत वर्षा का आंकड़ा छह इंच के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने जुलाई माह में भी 106 प्रतिशत से अधिक बारिश का अलर्ट जारी किया हैं।

इधर मौसम की बात करें तो मंगलवार को दिनभर बादल छाए रहे। सूरज बादलों के बीच छिपा रहा। हालांकि बारिश का इंतजार अधूरा रहा। बात अपने प्रदेश की करें तो अबकी बार मानसून की एंट्री सिर्फ 1 दिन लेट अर्थात 16 जून को हुई। इसके बाद मानसून जमकर बरसा और जून के कोटे से 40 प्रतिशत यानी 07 इंच से ज्यादा पानी गिर गया है। ग्वालियर-चंबल तरबतर हो गए। ऐसी ही उम्मीदें जुलाई से भी है। इस महीने पूरे मानसून की एक तिहाई यानी 12 से 15 इंच बारिश का ट्रेंड है। जैसे- भोपाल में 37.6 इंच सामान्य बारिश होती है तो 14 इंच बारिश जुलाई में होती है। बड़े शहरों में जबलपुर ही ऐसा है, जहां सबसे ज्यादा 17 इंच से ज्यादा बारिश होती है। मौसम विभाग भोपाल की सीनियर वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि इस बार जून में कोटे से ज्यादा पानी गिरा है। ऐसी ही बारिश जुलाई में भी होने की उम्मीद है। अगले 04 दिन पूरे प्रदेश में तेज बारिश का दौर रहेगा, जिससे जुलाई में भी कोटे से ज्यादा बारिश हो सकती है। 05 से 10 इंच बारिश वाले जिलों में सीहोर, राजगढ़, रायसेन, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, सिवनी, डिंडौरी, ग्वालियर, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, मुरैना, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, हरदा, शहडोल और उमरिया शामिल हैं।

पूर्व पार्षद लाला उर्फ धनराज चौधरी का कारनामा...

आवासीय क्षेत्र में दुकानें बनाकर दे दी किराए पर

जनसुनवाई में शिकायत, शहर के बंगला नंबर 18 कान्वेंट स्कूल के सामने मकान में छेड़छाड़ कर बना दिए आफिस-दुकान

नीमच, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। शहर के बंगला नंबर 18 कान्वेंट स्कूल के सामने आवासीय क्षेत्र में बने मकान के मूल स्वरूप में बदलाव कर दुकानें बनाकर किराए पर देने का मामला मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचा। नगरपालिका के अधिकारी-कर्मचारियों की सांठगांठ से लाला उर्फ धनराज चौधरी ने आवासीय जगह को व्यवसायिक में बदल दिया। इसके लिये न तो नगरपालिका से अनुमति ली गई और न ही नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से। शिकायत में लाला चौधरी के अवैध निर्माण तथा अतिक्रमण को जमींदोज कर व्यवस्थापन नहीं करवाने की दशा में नपा के कब्जे में लेने की मांग की गई है।

मंगलवार को जनसुनवाई में विक्की एलानी ने एडीएम श्रीमति लक्ष्मी गामड के समक्ष इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में उल्लेख किया कि पूर्व पार्षद लाला उर्फ धनराज चौधरी ने नपा से सांठगांठ कर नियमों का उल्लंघन किया है। नियमों के अनुसार भूखंड की 2400 वर्गफीट भूमि पर सिर्फ आवासीय उपयोग किया जा सकता है। लेकिन, लाला उर्फ धनराज चौधरी द्वारा मकान के मूल स्वरूप को ही बदल दिया है। शटर लगाकर कई दुकानें बना ली। एक दुकान में माइक्रो फायनेंस का आफिस संचालित हो रहा है, वहीं दूसरे में मेडिकल स्टोर्स भी चल रहा है।

बता दें कि शहर की बंगला-बगीचा क्षेत्र की जमीनों के लिए वर्ष 2017 में व्यवस्थापन बोर्ड लागू हुआ है और इसके लिए राजपत्र जारी हुआ है। किन्तु, 08 वर्ष बाद भी उक्त भूमि का व्यवस्थापन नहीं करवाया गया है। व्यवस्थापन के लिए लाला चौधरी द्वारा आवेदन भी नहीं लगाया गया है, ऐसी स्थिति में नियमों की अनदेखी करने व सालों बाद भी व्यवस्थापन नहीं करवाने की दिशा में उक्त संपत्ति पर नगरपालिका का अधिकार है। इसलिये नगर पालिका को उक्त संपत्ति को कब्जे में लेना चाहिए। मांग की गई है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सक्षम अधिकारी से करवाई जाए। क्योंकि, नगरपालिका के सांठगांठ से ही लाला चौधरी द्वारा मनमाफिक व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है।

पति-पत्नी के बीच विवाद, महिला ने फांसी लगाकर दी जान

नारायणगढ़, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। थाना क्षेत्र के पहेड़ा बालाजी मंदिर के पास एक महिला ने पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, आत्महत्या का कारण पति-पत्नी के बीच हुआ विवाद बताया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान हसीना बी पति हयात पठान निवासी पहेड़ा मगरा के रूप में हुई है। मंगलवार सुबह बेटे को स्कूल भेजने के दौरान पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद महिला घर से निकली और मंदिर के पास एक पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर नारायणगढ थाना प्रभारी अनिल रघुवंशी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीएम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नौवीं में एडमिशन के लिए 13 साल उम्र जरूरी

भोपाल, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। कक्षा नौवीं में एडमिशन के लिए 13 साल की उम्र पूरी करना जरूरी है। इससे पहले एडमिशन नहीं मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा नौवीं से लेकर 12 तक के प्रवेश की गाइडलाइन जारी की है। इसमें न्यूनतम उम्र की सीमा तय की गई है। एक जुलाई से ऑनलाइन नामांकन शुरू हो चुके हैं। नौवीं कक्षा के स्टूडेंट एक जुलाई से 30 सितबर तक नामांकन कर सकेंगे। मंडल प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। शुल्क 350 रूपए होगा। करीब 09 लाख स्टूडेंट ने पिछले साल ये फॉर्म भरे थे। 30 सितबर के बाद लेट फीस लगेगी। स्कूलों को मंडल ने इससे बचने के लिए पहले ही एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया कि वे स्टूडेंट से समय सीमा में फार्म जमा कराए।

शिक्षा नीति के मुताबिक आयु सीमा...

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक आयु सीमा है। छात्रों को नौवीं कक्षा में प्रवेश के लिए 01 अप्रैल तक कम से कम 13 वर्ष की उम्र पूरी करना होगा। 31 दिसंबर 2010 के बाद जन्मे छात्र 2024-25 शैक्षणिक सत्र में नौवीं कक्षा में दाखिला नहीं ले पाए थे। आठवीं कक्षा में पढ़ रहे स्टूडेंट इससे प्रभावित हो सकते हैं।

यह है गाइड लाइन के अनुसार आयु सीमा

नर्सरी	-	न्यूनतम 3 वर्ष, अधिकतम 4.5 वर्ष
केजी	-	1: न्यूनतम 4 वर्ष, अधिकतम 5.5 वर्ष
केजी	-	2: न्यूनतम 5 वर्ष, अधिकतम 6.5 वर्ष

अन्य कक्षाओं के लिए आयु मानदंड (1 अप्रैल तक)

रामघाट बैराज में मिला युवक का शव

मंदसौर, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। शहर के रामघाट बैराज में मंगलवार सुबह एक युवक का शव मिला। पानी में दिखाई देने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान मुकेश पिता पन्नालाल राठौर निवासी धानमंडी मंदसौर के रूप में हुई है। बताया गया है कि मुकेश सोमवार रात घर से निकला था और सुबह उनका शव नदी में मिला। शहर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए बड़े अस्पताल भेजा। जहां पीएम के पश्चात शव परिजनो के सुपूर्द कर दिया गया। कोतवाली टीआई पुष्पेंद्र सिंह राठौर के मुताबिक मुकेश राठौर मृत अवस्था में रामघाट बैराज में मिला है। फिलहाल मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों से पूछताछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति क्लीयर हो पाएगी।

मामला चार दिन पहले मिले महिला के शव का...

शादीशुदा प्रेमी के साथ रहने का बनाया था दबाव, विवाद के बाद प्रेमी ने धक्का देकर की हत्या

रतलाम, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। शहर में चार दिन पहले मिले 32 वर्षीय महिला के शव का मामला हत्या का निकला है। महिला के प्रेमी ने ही महिला से विवाद के बाद धक्का दिया था। जिससे वह सिर के बल गिर गई थी। सिर में चोट लगने पर उसकी मौत हो गई। प्रेमी उसे वहीं छोड़ कर चला गया था। आरोपी पहले से शादीशुदा है।

थाना औद्योगिक क्षेत्र में 27 जून की सुबह गांव जुलवानिया में मुंशी पाडा मार्ग पर एक महिला का शव मिला था। सिर पर चोट के निशान थे। महिला के पास से एक मोबाइल मिला था। जिससे उसकी शिनाख्त राधाबाई पति तेजराम निवासी रामपुरिया हाल मुकाम बाजना बस स्टैंड रतलाम के रूप में हुई थी। पुलिस जांच में जुट गई थी। जांच में पता चला कि राधा बाई के पति के रूप में तेजराम का नाम सामने आया, वह पति नहीं बल्कि प्रेमी है। राधाबाई और आरोपी तेजराम पिता रामाजी (रामपुरिया) थाना दीनदयाल नगर रतलाम के बीच प्रेम संबंध थे। राधाबाई, तेजराम के साथ रहने के लिए दबाव बनाती थी। इस कारण दोनों के बीच आए दिन विवाद होता था। पुलिस के अनुसार, महिला ने अपने पति को छोड दिया था। वर्तमान में वह लिव इन में बाजना बस स्टैंड रतलाम क्षेत्र में प्रेमी तेजराम के साथ रह रही थी। जबकि, प्रेमी तेजराम भी शादीशुदा है। उसकी एक बेटी भी है। तेजराम पत्नी और अपने बेटी के साथ रहना चाहता था। लेकिन, राधा बाई उसके साथ रहने का दबाव बनाती थी। दोनों 7-8 साल से लिव इन में रह रहे थे।

अवैध शराब पर कार्रवाई, 292 लीटर शराब जप्त, एक आरोपी गिरफ्तार

शामगढ़, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। शामगढ़ थाने की चौकी चंदवासा पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में 292 लीटर अवैध शराब जब्त की है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जबकि, एक अन्य फरार है। थाना प्रभारी धर्मेन्द्र शिवहरे के निर्देशन में कार्य कर रही टीम के प्रभारी उनि मनोज महाजन एवं उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

पहला मामला: हाथ भट्टी की कच्ची शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार- सोमवार को मुखबीर सूचना पर सउनि रुपसिंह झाला व उनकी टीम ने ग्राम असावती (बापच्या रोड) पर दबिश दी। मौके से आरोपी पुरसिंह पिता अनारसिंह निवासी ग्राम असावती को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 40 लीटर हॉफ ड्रम में भरी महुआ की कच्ची शराब एवं तीन प्लास्टिक केन (प्रत्येक में 10 लीटर) — कुल 70 लीटर हाथ भट्टी की अवैध शराब जप्त की गई। शराब की कीमत लगभग सात हजार रुपये आंकी गई हैं। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि घर में चल रहे मन्नत कार्यक्रम के लिए शराब बनाई गई थी। उसके विरुद्ध थाना शामगढ में अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है।

दूसरा मामला: स्विफ्ट डिजायर कार से 222 लीटर देशी-विदेशी शराब बरामद- मंगलवार को मुखबीर सूचना पर सउनि रुपसिंह झाला व उनकी टीम ने ग्राम घट्टिया-गरडा तिराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार को रोकने का प्रयास किया। कार चालक पुलिस को देख भागने लगा। लेकिन, अधिक गति और मोड पर नियंत्रण खोने से कार सडक किनारे खाई में पलट गई। कार चालक अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस ने मौके से कार की पिछली सीट व डिक्की से 14 पेटी देशी प्लेन शराब और 8 पेटी पावर बीयर (ऊजच कंपनी) कुल 222 लीटर शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 80 हजार 960 रुपये है, जब्त की। साथ ही स्विफ्ट डिजायर कार (अनुमानित कीमत 5 लाख रुपये) भी जब्त की गई। इस संबंध में भी थाना शामगढ में अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अज्ञात वाहन चालक पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

हेमंत खंडेलवाल बने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, औपचारिक घोषणा आज होगी

भोपाल, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। इसकी औपचारिक घोषणा बुधवार को की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हेमंत खंडेलवाल का नामांकन पत्र प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान चुनाव अधिकारी विवेक नारायण सेजवलकर को सरोज पांडे के समक्ष प्रस्तुत किया। वर्तमान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी हेमंत खंडेलवाल का नामांकन पत्र दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीरेंद्र कुमार खटीक, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवडा ने भी हेमंत खंडेलवाल के पक्ष में नामांकन पत्र दिया।

इनके अलावा राजेंद्र शुक्ला, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह ने भी पत्र दिया। कैलाश विजयवर्गीय नहीं पहुंचे। बुधवार को रहेंगे उपस्थित। यशपाल सिसोदिया ने भी नामांकन का प्रस्ताव दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने हेमंत खंडेलवाल के अलावा अन्य किसी अन्य के नाम के प्रस्ताव के लिए भी पूछा और इसके लिए 10 मिनट का समय दिया। इसके बाद राष्ट्रीय परिषद के नामांकन पत्र आमंत्रित किए गए। नामांकन पत्र देने वालों में मुख्यमंत्री मोहन, विष्णुदत्त शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, विरेंद्र खटीक, राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवडा, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, सावित्री ठाकुर, दुर्गादास उईके, फग्गन सिंह कुलस्ते, लाल सिंह आर्य, ओम प्रकाश धुर्वे, सत्यानरण जटिया, जयभान सिंह पवैया, जयंत मलैया, हिमाद्रि सिंह, भारती पराधी, इंदर सिंह परमार, सुधीर गुप्ता, नीना वर्मा, गणेश सिंह, कांत देव सिंह, गोपाल भार्गव, डा नरोत्तम मिश्रा, योगेश ताम्रकार, ब्रहेंद प्रताप सिंह, आलोक संजर, गौतम टेटवाल, कुंवर टैकम, गौरी शंकर बिसेन, उमा शंकर गुप्ता, कमल पटेल, ब्रजेंद्र पटेल, अर्चना चिटनीस, सुमेर सोलंकी कविता पाटीदार।

विचार-मंथन

पंजाब: क्या नशे के मुद्दे पर लड़ा जाएगा विस चुनाव?

पंजाब की राजनीति में पिछले कुछ सालों में नशा बड़ा मुद्दा रहा है। बुधवार को जब शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी हुई तो एक बार फिर नशे के मुद्दे को लेकर पंजाब की राजनीति में हंगामा शुरू हो गया है। मजीठिया को विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया है। विजिलेंस का आरोप है कि मजीठिया के खिलाफ ड्रग स्मगलिंग और हवाला कारोबार करने के सबूत मिले हैं। आरोप है कि मजीठिया ने 2007 से 2017 के बीच मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। आखिर पंजाब की राजनीति में पिछले कुछ सालों में बिक्रम सिंह मजीठिया और नशे का मुद्दा कैसे साथ-साथ गूंजता रहा है, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। आइए, चलते हैं। 2012 में नशा तस्करी का बड़ा मामला सामने आया था। इस मामले में 6000 करोड़ रुपए के सिंथेटिक ड्रग रैकेट का पता चला था और फतेहगढ़ साहिब में एफआईआर दर्ज की गई थी। उस वक्त राज्य में शिरोमणि अकाली दल-भाजपा की सरकार थी और मजीठिया इस सरकार में राजस्व मंत्री थे। मजीठिया तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के मंत्रिमंडल के ताकतवर नेता थे। बताना जरूरी होगा कि वह शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के साले भी हैं। 2012 की यह घटना 2014 में बहुत बड़ा मुद्दा बन गई क्योंकि तब पंजाब पुलिस से बर्खास्त डीएसपी जगदीश भोला ने इस मामले में अदालत में हाजिर होने के दौरान मजीठिया का नाम लिया। भोला भी इस मामले में आरोपी थे। भोला ने आरोप लगाया कि मजीठिया के ड्रग तस्करों के नेटवर्क के साथ संबंध हैं। एक और बड़ी घटना इस मामले में हुई। मार्च, 2016 में अकाली दल के पूर्व विधायक और मजीठिया के करीबी बोनी अजनाला ने तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को पत्र लिखा था। पत्र में अजनाला ने लिखा था कि उनके एक दोस्त मनिंदर सिंह बिट्टू औलख को 2012 के ड्रग स्मगलिंग केस में फंसाया गया है और ऐसा सुखबीर बादल और मजीठिया के दबाव की वजह से हुआ है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अजनाला के इन आरोपों को मुद्दा बना लिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में मजीठिया को पंजाब में नशे की मुख्य वजह बताकर प्रचारित किया और इसी के दम पर 2017 में कांग्रेस और 2022 में आम आदमी पार्टी ने राज्य में सरकार

बनाई। 2016 में मजीठिया ने आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और आशीष खेतान पर आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया। 2017 में कांग्रेस की सरकार बनी लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मजीठिया के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। इसे लेकर पार्टी में अंदरूनी लड़ाई भी दिखाई दी थी। अमरिंदर सिंह के बाद जब चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने दिसंबर 2021 में मजीठिया के खिलाफ नशे का केस दर्ज किया गया लेकिन इस मामले में पंजाब में उनकी भूमिका पर बात नहीं की गई थी और यह कनाडा में नशे के नेटवर्क पर था। यह मुकदमा 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दर्ज किया गया था और चुनाव प्रचार के बाद मजीठिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। मजीठिया 5 महीने तक पटियाला की जेल में रहे और अगस्त 2022 में उन्हें पंजाब और हरियाणा कोर्ट से जमानत मिली थी। याद दिलाना होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भगवंत मान ने मजीठिया पर निशाना साधा था और पंजाब के लोगों से कहा था कि कैसे ड्रग के मामले में आरोपी खुद को नशे से लड़ने वाला शख्स बता रहा है। 2022 के चुनाव में मजीठिया को अमृतसर ईस्ट सीट से हार का सामना करना पड़ा था हालांकि उनकी पत्नी को जीत मिली थी। पिछले कुछ महीनों में मजीठिया ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर पंजाब में बढ़ते नशे का आरोप लगाकर हमले तेज किए हैं। उन्होंने पंजाब सरकार के द्वारा नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम पर सवाल उठाए और सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो पोस्ट करके बताया कि पंजाब की सड़कों पर नशेड़ी घूम रहे हैं। यह साफ दिख रहा है कि मजीठिया की गिरफ्तारी और नशे का मुद्दा एक बार फिर पंजाब में जोर पकड़ रहा है।

मोदी सरकार ने आलू की खेती को नई दिशा देने का भरोसा जगाया

अमित शर्मा

बुधवार को मोदी कैबिनेट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसकी हलचल भले ही सोशल मीडिया पर कम दिखी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के गांवों की चौपालों पर बस इसी की चर्चा है। फैसला है आगरा के सींगना में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना का। यह खबर गुरुवार सुबह जैसे ही अखबारों में छपी, ब्रज क्षेत्र के कासगंज, एटा, हाथरस, अलीगढ़, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद और मथुरा के गांव-गांव में उम्मीद की नई लहर दौड़ गई। चौपालों पर इसे ऐसे बांटा जा रहा था जैसे कोई सपना अब आकार ले रहा हो। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद आलू के भविष्य की चमक इस इलाके के किसान-नौजवान की आंखों में साफ देखी जा सकती है। मोदी सरकार के इस कदम ने आलू की खेती को नई दिशा देने का भरोसा जगाया है। अब न सिर्फ आलू की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि इसका लाभ सीधे किसानों और युवाओं को मिलेगा। आगरा और आसपास के इलाकों में इसका असर दूरगामी होगा, जहां किसान बेहतर बीज, तकनीक और वैश्विक समर्थन से समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। इस फैसले ने बता दिया है कि सरकार की नजर अब गांवों पर भी है। यमुना किनारे 108 शिवालयों की श्रृंखला के आसपास बसे आगरा की तहसील बाह स्थित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के गांव बटेश्वर के निवासी राजकमल कहते हैं शहरी शोर में कई बार गांव की वो भावनाएं दबी रह जाती हैं, जो इस देश की आत्मा में बसती हैं। सींगना में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र (सीआईपी) के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (सीएसएआरसी) की स्थापना को मंजूरी देकर सरकार ने इस इलाके की ऐसी ही आत्मा की आवाज सुन ली है। उन्हें इस फैसले के बाद उम्मीद जागी है कि शायद अब आने वाले समय में यहां

का आलू किसानों का 'भाग्यविधाता' होगा। राजकमल को उम्मीद है कि कई बार अधिक फसल होने, समय से पहले ही कोल्ड स्टोरेज फुल हो जाने और कीमतों में भारी गिरावट के चलते खून-पसीने से उगाई फसल किसान सड़कों पर फेंकने को मजबूर हो जाते थे, शायद अब ऐसा नहीं होगा। सीएसएआरसी की स्थापना से आलू को नई पहचान, बड़ा बाजार और उचित कीमत मिलेगी। यमुना और चंबल के बीच में मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा से सटे और कभी दस्यु प्रभावित रहे इसी इलाके के पिनाहट के किसान राम सुंदर बीते 30 वर्षों से लगभग 300 बीघे में आलू की खेती करते आ रहे हैं। उनके ट्यूबवेल पर बैठे तमाम काश्तकारों के चेहरे भी आलू की कीमतों की लगातार अनिश्चितता के भाव से मुक्ति पाते नजर आए। राम सुंदर व तमाम काश्तकारों का कहना था कि उनका पूरा क्षेत्र दशकों से आलू की खेती कर रहा है लेकिन हमेशा एक अनिश्चितता उनके दिल-दिमाग में बनी रहती थी कि जो काम वो कर रहे हैं उसका क्या भविष्य होगा? सरकार के इस फैसले ने उनको इस अनिश्चितता से मुक्ति दी है और एक सुरक्षा का आभास करा दिया है। इन किसानों में विश्वास जगा है कि अब आने वाले समय में आलू ही सबकी किस्मत बदलने वाला है। प्रमुख वैज्ञानिक एवं विभागाध्यक्ष, कृषि विज्ञान विभाग (एग्रोनॉमी) आईएआरआई-पूसा, नई दिल्ली व विश्व बैंक में भारत सरकार के राष्ट्रीय समन्वयक (कृषि), डॉ. संजय सिंह राठौर कहते हैं कि विदेशी किस्मों के आलू बीज अब कंद नहीं बल्कि ट्रांसप्लांटेशन तकनीक से तैयार होंगे और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र अब आगरा में स्थापित होगा, ये दोनों ऐतिहासिक निर्णय देश की कृषि तकनीक और खाद्य सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। ये फैसले सिर्फ एक फसल की नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, निर्यात रणनीति और किसान सशक्तिकरण की पूरी श्रृंखला को प्रभावित करेंगे। साथ ही उनका कहना है कि इस अनुसंधान केंद्र से बीज क्रांति की भी नई शुरुआत होगी जो आलू किसानों के भविष्य को बदल कर रख देगी। कोल्ड स्टोरेज संचालक प्रशांत पाठक कहते हैं कि अब तक आगरा को ताजनगरी के नाम से जाना जाता था लेकिन अब 'आलू टेक्नोलॉजी' भी मान बढ़ाएगी। अब बात आती है कि सीएसएआरसी की स्थापना के बाद तकनीकी तौर पर क्या बदल जाएगा। दरअसल परंपरागत रूप से भारत में 'आलू बीज' पुराने कंदों से ही तैयार होते हैं जो बार-बार इस्तेमाल से वायरस ग्रस्त होकर उत्पादन घटाते हैं। इसके बाद ट्रांसप्लांटेशन विधि यानी सूक्ष्म पौधों से बीज तैयार किए जाएंगे-जिससे उच्च गुणवत्ता, रोग प्रतिरोधकता और एकरूपता सुनिश्चित होगी। यह प्रणाली वैश्विक स्तर पर टीपीएस के समान है जो न केवल भंडारण क्षमता में सुधार करती है, बल्कि 20-30प्रतिशत तक अधिक उपज भी देती है। इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी और आलू उत्पादन में वायरस और फफूंदजनित नुकसान घटेगा। सीएसएआरसी चीन, केन्या, और पेरू के बाद दुनिया का चौथा प्रमुख आलू अनुसंधान केंद्र होगा। इसकी लागत 111-171 करोड़ होगी और यह 10 हेक्टेयर में फैलेगा।

केंद्र के प्रमुख उद्देश्य:

जलवायु अनुकूल और पोषण संपन्न आलू/शकरकंद की नई किस्में विकसित करना।

बीज उत्पादन व संवर्धन तकनीकों पर काम।

कीट नियंत्रण, मूल्य संवर्धन, और किसान प्रशिक्षण।

निर्यात योग्य प्रोसेसिंग ग्रेड आलू विकसित करना।

क्यों चुना गया आगरा?

उत्पादन केंद्र: अकेले आगरा जिले में हर साल 50 लाख टन से अधिक आलू का उत्पादन होता है, जो यूपी के कुल उत्पादन का 27प्रतिशत है।

बीज की भारी मांग: सिर्फ आगरा में हर साल करीब 7 लाख टन बीज आलू की जरूरत होती है।

भौगोलिक श्रेष्ठता: यहां की जलवायु, मिट्टी और सिंचाई सुविधा अनुसंधान के लिए उपयुक्त है।

यूपी की स्थिति: यूपी देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है, जो देश के 35त्र उत्पादन के लिए जाना जाता है।

खाद्य सुरक्षा से लेकर निर्यात तक

खाद्य सुरक्षा: गेहूं और चावल के बाद आलू भारत की तीसरी सबसे अहम फसल है। 2020 में भारत का आलू उत्पादन 51.3 मिलियन टन था जो अब और तेजी से बढ़ रहा है।

किसानों की आमदनी: बेहतर बीज, नई किस्में और ट्रांसप्लांटेशन तकनीक से किसान की प्रति हेक्टेयर आमदनी में 25-40प्रतिशत तक वृद्धि संभव है।

निर्यात अवसर: 2050 तक भारत का आलू उत्पादन 100 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है जो भारत को चीन से आगे निकाल सकता है। प्रोसेस्ड फॉर्म (चिप्स, फ्राइज, स्टार्च) में निर्यात संभावनाएं कई गुना अधिक होंगी।

मिजोरम की शिक्षा यात्रा भारत के लिए सबक...

राजेंद्र जोशी

व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा और विकास एक दूसरे के पूरक है। प्रत्येक एक दशक बाद भारत में जनगणना होती है। जनगणना के आंकड़ों से साक्षरता दर का आकलन होता है। आजादी के बाद 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद साक्षरता के क्षेत्र में तेज गति से काम होने लगा। 2001 से 2011 के दशक में साक्षरता की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ। इस दौरान अनेक प्रदेशों की साक्षरता दर में उछाल आया। इस दशक में साक्षरता के क्षेत्र में उत्तर भारत में उत्साह और उमंग के साथ सराहनीय काम हुआ, जहां साक्षरता प्रतिशत पचास फीसद से भी कम था। उस दौरान केरल 93.91 फीसद साक्षरता दर के साथ देश में नंबर एक पर था तो मिजोरम 91.58 फीसद साक्षरता दर के साथ तीसरे स्थान पर था। अब आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीएफएलएस रपट के मुताबकि, मिजोरम 98.20 फीसद साक्षरता दर हासिल कर देश का पहला पूर्ण साक्षर प्रदेश बन गया। संपूर्ण साक्षरता अभियान के बाद उत्तर साक्षरता अभियान और सतत शिक्षा कार्यक्रम संचालित होने लगे और धीरे-धीरे साक्षरता अभियानों ने कार्यक्रम का स्थान ले लिया। यहीं से साक्षरता कार्यक्रम बन गया और साक्षर होने की गति और उत्साह भी कम होने लगा। मिजोरम में फिर से साक्षर होने की कार्ययोजना तैयार कर उल्लास कार्यक्रम के तहत फिर वही प्रक्रिया अपनाई गई। निरक्षर व्यक्ति को केवल साक्षर बनाना ही मकसद नहीं होता, नवसाक्षरों का शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास करना होता है। यह बात मिजोरम ने समझी। प्रदेश के आर्थिक स्तर को सुधारने, भविष्य उन्नयन और नवसाक्षरों को व्यावसायिक कौशल देने के प्रयास भी किए। संपूर्ण साक्षरता अभियान की तरह सरकार ने जनता के सहयोग से निरक्षरता उन्मूलन के लिए स्वयंसेवक तैयार किए, उन्हें प्रशिक्षण दिया, शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई, स्वयंसेवकों के साथ सरकार के प्रतिनिधि और अफसर नियमित संपर्क में बने रहे। प्रदेश भर में साक्षरता के पक्ष में वातावरण बनाया गया, वातावरण निर्माण के तहत घर-घर सर्वेक्षण किया गया, लोगों को आमंत्रित किया गया, असाक्षरों का सम्मान किया गया। उनके साथ निरंतर संपर्क रखा गया। इस कार्यक्रम में असाक्षर की पहचान, मूल्यांकन और

निरीक्षण का काम प्रतिदिन होता रहा। क्लस्टर बनाकर क्षेत्र आधारित कार्यक्रम तैयार किए गए। छोटे-छोटे समूह बनाए गए, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद और समाज के व्यक्ति, जो साथ मिलकर असाक्षर व्यक्ति के घर जाते, उनसे आग्रह करते। समुदाय के सहयोग से संचालित साक्षरता अभियान के अंतर्गत स्थानीय भाषा और गहरी सांस्कृतिक सहायता से लोगों ने सिर्फ पढ़ना ही नहीं सीखा, बल्कि ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जो ज्ञान को महत्त्व देने लगे। शिक्षित नागरिक से ही एक समग्र और विकसित राष्ट्र और समाज की परिकल्पना की जा सकती हैं। यह अच्छी और सुखद खबर है। मिजोरम की साक्षरता यात्रा देश के अन्य प्रदेशों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। 2011 में 91.58 फीसद लोग साक्षर थे। कहने को यह भी कहा जा सकता है कि केवल आठ फीसद लोगों को ही साक्षर करने का काम था। दिखने में और सुनने में आठ फीसद का लक्ष्य तय करना कोई बड़ी बात न हो, पर यही वह समूह था, जिसको साक्षर करना मुश्किल काम था। शिक्षा से दूर रहे इस समूह की मानसिकता बदलना मुश्किल ही नहीं कठिन काम होता है, जिसे मिजोरम ने अपनी इच्छा शक्ति से कर दिखाया। नब्बे के दशक में केरल संपूर्ण साक्षर घोषित किया गया था। केरल से पहले एर्नाकुलम जिले को संपूर्ण साक्षर घोषित किया गया था। वहां भी संपूर्ण साक्षरता अभियान को जन आंदोलन बनाया गया था। केरल सरकार ने भारत ज्ञान विज्ञान समिति के साथ मिलकर यह काम किया। वहां भी उस समय केवल नौ फीसद लोगों को ही साक्षर करना था, लेकिन वे भी 'हार्डकोर ग्रुप' यानी शिक्षा से दूर रहे समूह की श्रेणी में थे। केरल की साक्षरता यात्रा घर, गांव और जिला स्तर तक चली। केरल में प्रत्येक सरकारी अधिकारी जन सहयोग से अपनी जिम्मेदारी समझकर निरक्षरता उन्मूलन के पवित्र काम में लगा था।

बाढ़ज़नित हादसों में कब तक होती रहेगी जन-धन की हानि

भारत में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान में तेजी से वृद्धि हुई है। 2013-2022 के दशक में हर साल औसतन 8 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 66,000 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। यह 2003-2012 के दशक की तुलना में 125 फीसदी अधिक है, जब यह आंकड़ा 3.8 अरब डॉलर था। देश में सरकारी मशीनरी की तंद्रा तब भंग होती है, जब कोई बड़ा हादसा हो जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी तंत्र जागने के लिए बड़े हादसे की इंतजार में रहता है। पहले हुए हादसों से सबक सीखने की जरूरत महसूस नहीं की जाती। इसकी प्रमुख वजह है जिम्मेदारी का अभाव। यदि यह जिम्मेदारी तय कर दी जाए कि किसी तरह के हादसे के जिम्मेदारी संबंधित विभागों के अफसरों की होगी और हादसा होने की सूरत में उन्हें सख्त सजा मिलेगी, तभी हादसों पर लगाम लगाई जा सकती है। अभी मानसून की शुरुआत है। हर साल मानूसन के दौरान देश में बाढ़ जनित हादसों में सैकड़ों लोगों की मौत होती है। भारी बारिश से देश को अरबों रुपयों की सम्पत्ति का नुकसान होता है। जन-धन की इस हानि की किसी जिम्मेदारी तय नहीं है। आखिर कौन हर साल होने वाले ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार है। हादसा होने के बाद सिर्फ लकीर पीटी जाती है। ऐसे उपाय नहीं किए जाते कि हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो, या फिर इनकी संख्या में कमी लाई जा सके। भारत में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान में तेजी से वृद्धि हुई है। 2013-2022 के दशक में हर साल औसतन 8 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 66,000 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। यह 2003-2012 के दशक की तुलना में 125 फीसदी अधिक है, जब यह आंकड़ा 3.8 अरब डॉलर था। वर्ष 2024 के नुकसान की गणना अभी बाकी है, जो इतिहास में भारत का सबसे गर्म साल रहा है। यह वृद्धि बताती है कि या तो प्राकृतिक आपदाएं अधिक बार आ रही हैं, अधिक गंभीर हो गई हैं, या दोनों ही बातें हो रही हैं। 1970 से 2021 तक का डेटा दिखाता है कि समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कुछ वर्षों में नुकसान की मात्रा में बड़ी छलांग देखी गई, जो विनाशकारी घटनाओं, जैसे कि बड़े चक्रवातों, बाढ़, या सूखे के कारण हुई। वर्ष 2023 में, भारत को प्राकृतिक आपदाओं से 12 अरब अमेरिकी डॉलर (एक लाख करोड़ रुपये से अधिक) का नुकसान हुआ। यह 2013-2022 के औसत 8 अरब डॉलर से काफी ज्यादा था। स्विस रे की रिपोर्ट के अनुसार, ये बड़े नुकसान उन क्षेत्रों में हुए जहां संपत्तियों और आर्थिक गतिविधियों की संख्या ज्यादा है। स्विस रे एक प्रमुख पुनर्बीमा कंपनी है, जो विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट और अध्ययन प्रकाशित करती है। जून 2023 में, चक्रवात बिपरजॉय ने गुजरात के कच्छ जिले में भारी नुकसान पहुंचाया। इसके कारण सौराष्ट्र और कच्छ के सभी बंदरगाह, जैसे कांडला और मुंद्रा बंदरगाह, बंद हो गए। तेज हवाओं, भारी बारिश और समुद्री तूफान ने राज्य में भारी तबाही मचाई। इस चक्रवात ने महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों को भी प्रभावित किया। दिसंबर 2023 में, चक्रवात मिचाउंग के चलते चेन्नई में भारी बारिश और बाढ़ के कारण बड़े नुकसान हुए। इसके अलावा, जुलाई 2023 में उत्तरी भारत और सिक्किम में आई बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को बुरी तरह प्रभावित किया। स्विस रे के विश्लेषण में पाया गया कि भारत में पिछले दो दशकों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले कुल वार्षिक नुकसान का लगभग 63 फीसदी हिस्सा बाढ़ से जुड़ा हुआ है।

आज का राशिफल

मेष : [illegible]

वृषभ : [illegible]

मिथुन : [illegible]

कर्क : [illegible]

सिंह : [illegible]

कन्या : [illegible]

तुला : [illegible]

वृश्चिक : [illegible]

धनु : [illegible]

मकर : [illegible]

कुंभ : [illegible]

मीन : [illegible]

सुडोकू पहेली क्रमांक- 5644

			7		9		2	
		9	2	1	6			5
5			8		4			
	6					4		
3	7			4			6	1
		2					5	
			9					3
7			3	8	5	2		
	3		4		1			

नियम : प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक अंक भरे जाने आवश्यक हैं, इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी व खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में अंक की पुनरावृत्ति न हो, पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।

सुडोकू पहेली क्र. 5643

8	5	3	2	4	1	6	9	7
9	4	2	6	5	7	8	1	3
1	7	6	9	8	3	2	4	5
5	6	9	4	7	2	1	3	8
2	3	4	8	1	5	9	7	6
7	8	1	3	6	9	4	5	2
6	9	7	5	2	4	3	8	1
4	2	5	1	3	8	7	6	9
3	1	8	7	9	6	5	2	4

वर्ग पहेली 5644

संकेत: बाएं से दाएं
1. 27 सितंबर 1949 को बीजिंग शहर को इस देश की नई राजधानी चुना गया (2)
4. जिंदगी, पुरानी फिल्मों के दिवंगत खलनायक एवं चरित्र अभिनेता (3)
6. कामयाब न होना, असफल होना (6)
9. एशिया के दक्षिणी पूर्वी तट से करीब 900 किमी.दूर विषुवत रेखा पर स्थित देश फिलीपींस की यह राजधानी है (3)
10. जो, अगर (2)
11. अलंकरण, रूप, चित्र (2)
12. अध्ययन करने की क्रिया को अंग्रेजी में यह कहते हैं (2)
15. बल, मरोड़, ऐंठ, खम (3)
16. चकवा पक्षी को यह भी कहा जाता है (4)
18. धनमान, ईकम, आमदनी (2)
19. यह अरब राज्य 15 अगस्त 1971 को स्वाधीन हुआ था (4)
20. अधीनता, मातहती, अधिकार, वश (3)

ऊपर से नीचे
1. मुख्यमंत्री को अंग्रेजी में यह कहते हैं (6)
2. ओरायन की मेखला का एक सितारा, नाम जल प्राप्ति का कृत्रिम स्रोत (2)
3. आकाशीय विद्युत, बिजली, तड़ित (3)
4. जीवित रहना, सजीव रहना (2)
5. इस फिल्म में संजीव कुमार ने नौ भूमिकाएं निभाई थीं (8)
7. लवण, क्षौर, खारे जल से तैयार किया गया क्षार पदार्थ (3)
8. माथा, मस्तक, भाल (3)
10. हिंदी साहित्य में एक अलंकार जिसमें एक ही शब्द बार-बार आकर भिन्न-भिन्न अर्थ देता है (3)
13. किसी महाविद्यालय का प्रमुख, प्रिंसिपल, किसी विश्वविद्यालय में संकायाध्यक्ष (2)
14. नायक, किसी नाटक फिल्म का प्रमुख पात्र (2)
15. उपालंभ, शिकायत (4)
17. उपस्थिति, हाजिर होने का भाव (3)

वर्ग पहेली 5643 का हल

हे	प	आ	ने	ह			
प	र	मा		ही	र	सं	इ
की		ग्रा	या		फा		र
शु	ह	मा	रा	फ	र		सं
त	ल		प			ते	र
		आ	द	म		अ	
ल	ह	द	रा		ते	भ	ना
ला	न	र			क	र	ना

अन्य लेब की जांच रिपोर्ट को किया जा रहा खारिज-शर्मा

पैथोलॉजी जांच में डॉक्टर्स के कमीशन से आमजन परेशान

मंदसौर, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांत सह सचिव नवनीत शर्मा ने शहर में हो रही निजी पैथोलॉजी लेब की लूटपाट को लेकर निजी डॉक्टर्स व पैथोलॉजी पर गंभीर आरोप लगाए हे। नवनीत शर्मा ने प्रेस वक्तव्य के माध्यम से बताया कि हाल ही में शहर सहित आसपास के श्रेत्र में पैथोलॉजी जांच को लेकर आमजन को कई परेशानी का सामना करना पड रहा हैं। डॉक्टरों द्वारा जांच के लिए कुछ चुनिंदा लैब्स की ही सिफारिश करना और अन्य पैथोलॉजी की रिपोर्ट को मान्यता न देना अब एक आम समस्या बन गई है। इसके पीछे कमीशनखोरी की बात सामने आ रही है, जिससे मरीजों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड रहा है।कमीशनखोरी के कारण निजी पैथोलॉजी लेब की दर कई गुना बढती ही जा रही हे।जिसका सीधा असर आम ग्राहकों पर पड रहा है।

देखने में यह भी आया हे कि कई डॉक्टर विशेष लैब की सिफारिश कर मरीजों को वहां भेजते हे।कई ग्राहकों ने ग्राहक पंचायत को बताया कि है कि अधिकांश निजी डॉक्टर जांच के लिए विशेष पैथोलॉजी लैब्स की सिफारिश करते हैं, परंतु हम कई अन्य जगह जांच कराते हे तो डॉक्टर्स द्वारा उस जांच को मान्य नहीं किया जाता और कहा जाता की जहां की जांच लिखी वही कराओ।इस तरह यदि मरीज किसी अन्य सस्ती या विश्वसनीय लैब से जांच करवाता है, तो डॉक्टर उस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर देते हैं और दोबारा जांच की सलाह देते हैं।इस रवैये से न सिर्फ मरीजों को आर्थिक नुकसान उठाना पडता है, बल्कि समय और स्वास्थ्य दोनों की हानि होती है। कुछ मरीजों ने बताया कि एक ही जांच के लिए उन्हें दो-दो बार पैसे खर्च करने पडे क्योंकि डॉक्टर ने उनकी पहली रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया।इस मामले की जानकारी स्वास्थ्य विभाग में बैठे उच्च स्तर के अधिकारियों को भी हे परंतु मिलीभगत से आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई हे। इस तरह की शिकायतें लगातार बढ रही हैं, बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मेडिकल एथिक्स के खिलाफ ऐसा व्यवहार मरीजों के अधिकारों का हनन है।स्वास्थ्य क्षेत्र से जुडे विशेषज्ञों का कहना है कि डॉक्टरों का मरीजों पर लैब थोपना न केवल गैर-जरूरी है, बल्कि इससे मेडिकल पेशे की गरिमा भी धूमिल होती है। यह आवश्यक है कि मरीजों को अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुसार पैथोलॉजी चुनने का अधिकार मिले।पैथोलॉजी जांच में पारदर्शिता लाने और डॉक्टरों व लैब्स के बीच चल रही कमीशन प्रथा को रोकने के लिए प्रशासन को जल्द ही ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और स्वास्थ्य सेवाओं में भरोसा कायम रह सके। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आम ग्राहकों से आह्वान करती हे कि यदि शहर में इस तरह से जानबुझकर यदि ग्राहकों का शोषण किया जाता है तो इसकी जानकारी तुरंत जिला प्रशासन या ग्राहक पंचायत को दे।

श्रावण मास नजदीक, लेकिन अभी तक नहीं हटाई गई अवैध मांस-मछली की दुकानें -श्रीवास्तव

मंदसौर, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। समाजसेवी सरदार कुणाल श्रीवास्तव ने बताया कि 11 जुलाई से श्रावण मास शुरू हो रहा है लेकिन बार-बार जिम्मेदारों का ध्यान आकर्षण करने के बाद भी भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर की पवित्र नगरी मंदसौर से मांस-मछली की दुकानों को मंदसौर नगर से नहीं हटाया गया है जिससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही है।

सरदार कुणाल श्रीवास्तव ने बताया कि उनके द्वारा जनसुनवाई में भी विगत मंगलवार को इस बाबत् आवेदन दिया गया था लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जबकि मंदसौर जो भगवान पशुपतिनाथ की पवित्र नगरी है, इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने मंदसौर नगर में शराब बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है लेकि शराबबंदी के साथ-साथ मांस, मटन, मछली आदि का व्यापार धडल्ले से चालू है जिससे पवित्र नगरी पर इन नानवेज पदार्थों क्र अवैध से रूप से विक्रय धार्मिक नगरी की पवित्रता को भंग कर रहा है। इन दुकानों के धडल्ले से चलने के कारण नागरिकों की धार्मिक भावनाएँ भी आहत हो रही हैं। यहां यह भी देखने में आ रहा है कि कई ऐसे व्यापारी भी है जो बिना लाइसेंस के खुले आम अपनी दुकानों पर मांस, मछली का व्यापार कर रहे है। यहां पर उनके द्वारा स्वच्छता का ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है जो कभी भी गंभीर घटना को बुलावा दे सकता है। मंदसौर के पवित्र व प्रसिद्ध स्थल भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच मार्ग पर सर्वाधिक नॉनवेज दुकाने संचालित हो रही है। इस मार्ग से दर्शनार्थी मंदिर पहुंचते है। सावन मास में कावडा यात्री आते हैं। भगवान श्री पशुपतिनाथ की विशाल शाही सवारी भी इसी मार्ग से निकलती है बावजूद इसके धानमण्डी से लेकर पशुपतिनाथ की नवीन पुलिया तक कई नॉनवेज की दुकाने संचालित हो रही है। यहां भी असामाजिक तत्वों का जमावडा भी रहता है तथा यहां पर अवैध रूप से शराब भी विक्रय होती है इस बाबत् कई बार नागरिकों ने इनको हटाने के लिये आवेदन भी दिये गये है। लेकिन अभी तक इनको नहीं हटाया गया है। अत: यहां से इन नॉनवेज व्यापारियो को हटाया जाये तथा अवैध रूप से संचालित दुकानों पर कार्यवाही की जाये।

श्रीवास्तव ने कहा कि दूसरी और कैलाश मार्ग से कोर्ट रोड होते हुए भी श्री पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचने का मार्ग स्थित है। इस मार्ग से भी बाहर से आने वाले श्रद्धालु व कावड यात्री मंदिर पहुंचते है। यहां भी मछली मार्केट संचालित होता है। यहां पर मंदसौर शहर सहित बाहर से भी बडी संख्या में व्यापारी आकर मछली का क्रय-विक्रय करते है। अनेक व्यापारी ऐसे भी है जिनके पास मछली व्यापार का लायसेंस नहीं है। लेकिन लाखों रूपयों की चोरी की मछलियों का यहां व्यापार होता है। यहां से खुलेआम मछलिया को क्रय कर रात्रि में बसों द्वारा व निजी वाहनों व ट्रेनों के माध्यम से यह मछलिया अन्य राज्यों में भेजी जा रही है। मछलियों का अवैध रूप से कारोबारी कई बार झगडा कर मंदसौर का वातावरण भी खराब कर चुके है तथा खूनखराबा भी हो चुका है। अत: इन पर सख्ती से रोक लगाई जाए। तथा कैलाश मार्ग स्थित मछली मार्केट के बाहर रोड पर कई बार मरी हुई मछलियां भी पडी होती है तथा इस क्षेत्र में भयंकर बदबू भी आती है। जिससे भी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। अत: यहां से मछली बाजार हटाया जाये तथा अवैध व्यापार करने वालों पर कार्यवाही की जाये। श्रीवास्तव ने प्रशासन से मांग की कि जनहित में इस विषय पर त्वरित संज्ञान लेते हुए, नगर में मांस-मछली की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी करें तथा मांस मछली की दुकानों व मछली मार्केट को शहर से बाहर स्थानांतरित करने तथा अवैध व्यापारियों पर कार्यवाही का आदेश प्रदान करे।

कलेक्टोरेट में सामुहिक राष्ट्रगान एवं वन्दे मातरम का गायन

नीमच, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। कलेक्टर कार्यालय नीमच में मंगलवार को सामुहिक राष्ट्रगॉन एवं वंदेमातरम का गायन किया गया। राष्ट्रगॉन म.प्र.गान एवं वन्देमातरम का गायन ए.डी.एम.श्रीमती लक्ष्मी गामड तथा जिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में हुआ।

इस अवसर पर ए.डी.एम.श्रीमती लक्ष्मी गामड ने म.प्र.जल निगम परियोजना क्रियान्वयन ईकाई नीमच की प्रबंधक तकनीकी सुश्री सोनम चौहान को बेस्ट एम्पीलॉई ऑफ दी मंथ के पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार सुश्री सोनम चौहान को गांधीसागर-2 समूह जल प्रदाय योजना का निर्माण कार्य इंटेकवेल, जल शोधन संयंत्र, उच्चन स्तरीय टंकियों के निर्माण कार्य, पाईप लाईन बिछाने के कार्य एवं रोड रेस्टोरेशन कार्य के निरीक्षण एवं सहायक एजेंसियों से संमन्वय कर गुणवत्तापूर्व कार्य समय सीमा में पूर्ण कराने के हर संभव प्रयासों के फलस्वरूप प्रदान किया गया है। सुश्री सोनम चौहान ने सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों के निराकरण में रूचि लेकर ग्रामीणजनों से सम्पर्क कर, समस्याओं का समाधान करवाने पर यह सम्मान प्रदान किया गया हैं। सुश्री चौहान को एडीएम श्रीमती गामड ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर, बेस्ट एम्पलॉई आफ दी मंथ के पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर संयुक्त कलेक्टर डॉ.ममता खेडे, डिप्टी कलेक्टर श्री चंद्रसिंह धार्वे, श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव एवं कलेक्टोरेट भवन स्थित सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों ने सामुहिक रूप से राष्ट्रगॉन, वंदे मातरम एवं म.प्र.गॉन का गायन किया। तदपश्चात जुलाई माह में शासकीय कार्यो की शुरूआत की गई। इस अवसर पर कलेक्टोरेट, राजस्व, भू-अभिलेख, श्रम, सहकारिता विभाग, शिक्षा, कोषालय, जनसम्पर्क कार्यालय, शहरी विकास अभिकरण सहित विभिन्न विभागों के बडी संख्या में अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।

सेवानिवृत्त कर्मचारी समाज के लिये समर्पित भाव से कार्य करे

मंदसौर, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपने को समाज की सेवा के लिये समर्पित करे और जीवन में समाज हित में कार्य करते हुए घर परिवार ही नहीं अपितु राष्ट्र के हित का चिंतन करते हुए समाज हित के विचार को सर्वप्रथम रखे।

उक्त विचार नपाध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर ने नपा की जलकार्य शाखा में लाईनमेन के पद पर कार्यरत रहे श्री बद्रीलाल भावसार की सेवानिवृत्ति के अवसर पर कहे। आपने श्री भावसार की सेवानिवृत्ति पर उनका शाल, श्रीफल भेंटकर व माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया और उन्हें शेष जीवन में सुखी सम्पन्न रहने हेतु शुभकामनायें दी। इस अवसर पर नपा जलकार्य समिति सभापति निलेश जैन, सीएमओ श्रीमती अनिता चोकोरिया, नपा सभापति रमेश ग्वाला, जलकार्य समिति सदस्य एवं पार्षद श्रीमती सुनीता अशोक भावसार, श्रीमती सुनीता नंदलाल गुजरिया, गोवर्धन कुमावत, कमलेश सिसौदिया, पूर्व पार्षद राकेश भावसार, नपा कार्यपालन यंत्री पी.एस. धारवे, नपा कार्यालय अधीक्षक अजय मारोठिया, नपा जलकार्य शाखा लिपिक मो. शाहिद, पंच कचेरिया राठौर समाज अध्यक्ष राजू राठौर सहित कई गणमान्य नागरिकगण एवं नपा की जलकार्य शाखा के कर्मचारीगण भी उपस्थित थे। यह उल्लेखनीय है कि श्री बद्रीलाल भावसार, नपा कार्यालय में लगभग 40 वर्षों से सेवा में रहे तथा कई वर्षों से नपा की पेयजल व्यवस्था देख रहे थे।

जनजातीय विद्यार्थियों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

नीमच, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार कक्षा 9 वी से महाविद्यालय स्तर तक अध्ययनरत विद्यार्थियों जिन्हें केन्द्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (वार्षिक पारिवारिक आय सीमा रूपये 2.50 लाख से कम) का लाभ प्राप्त होता है, उन्हें वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों द्वारा एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लिए जाने के बाद भविष्य में भी आगामी कक्षाओं में इसी नंबर के आधार पर छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभप्राप्त हो सकेगा, जिसके लिये पृथक से पुन: वन टाइम रजिस्ट्रे शन कराने की आवश्यकता होगी।

जिला संयोजक श्री राकेश कुमार राठौर ने बताया, कि कक्षा 9 वी से महाविद्यालय स्तर तक अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने की प्रकिया दो चरणो में होगी। प्रथम चरण में विद्यार्थियों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट से अथवा मोबाइल पर एनएसपी ओटीआर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर उसमें आवश्यक जानकारी दी कर रेफरेंस नंबर प्राप्त करना होगा। द्वितीय चरण में एनएसपी ओटीआर एप एवं आधार फेस आरडी सर्विस एप डाउनलोड कर रेफरेंस नंबर के माध्यम से ओटीआर की प्रकिया कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना होगा। एम.पी.टास्क पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन करते समय विद्यार्थी को ओटीआर नंबर देना अनिवार्य होगा। श्री राठौर ने कक्षा 9वीं से महाविद्यालय स्तर तक अध्ययनरत जिले के सभी जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों से नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराने का अनुरोध किया है।

गणित के 04 विद्यार्थियों का एमपी पीएससी में चयन

मंदसौर, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मन्दसौर के प्राचार्य प्रो. जे.एस. दुबे ने जानकारी देते हुऐं बताया कि महाविद्यालय के गणित विषय के 04 विद्यार्थी डॉ. बालाराम कलेसरिया, श्री विनोद पाटीदार, डॉ. प्रिया बघेल एवं श्री गजेन्द्र आर्य का म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा में चयन हुआ है। महाविद्यालय की इस उपलब्धि पर जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री नरेशजी चंदवानी, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. जे.एस. दुबे, वरिष्ठप्राध्यापक डॉ. डी.सी. गुप्ता, गणित विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. टी.के. झाला तथा महाविद्यालय परिवार ने विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाऐं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

लोक निर्माण विभाग पूरे जिले में चलाएगा पौधरोपण महाअभियान

मंदसौर, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। लोक निर्माण विभाग द्वारा मंदसौर सर्किट हाउस में पौधरोपण कर पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान पूरे 1 जुलाई से मंदसौर जिले में चलाया जाएगा। जिसमें विभाग के रेस्ट हाउस व गेस्ट हाउस सहित अन्य स्थानों पर पौधे रोपे जायेंगे।

लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री नितेश सुलिया ने इस दौरान बताया कि माननीय मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में 1 जुलाई से पौधरोपण महाअभियान की शुरुआत की गई जिसके तहत पूरे प्रदेश में 1 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के तहत मंदसौर जिले में करीब 1200 पौधे रोपे जायेंगे। जिसका शुभारंभ रेस्ट हाउस मंदसौर में पौधारोपण किया गया है। यह अभियान जिले के मंदसौर, पिपलियामंडी, नारायणगढ, दलौदा, गरोठ सहित अनेक स्थानों पर यह अभियान चलाया जाएगा तथा पौधे रोपे जायेंगे। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण ने उपस्थित होकर पौधरोपण में भाग लिया।

नपाध्यक्ष ने नपा की जलकार्य समिति के साथ श्री होरी हनुमानजी के दर्शन किये

मंदसौर, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। नपाध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, नपा जलकार्य समिति सभापति श्री निलेश जैन ने जलकार्य समिति के सदस्यों के साथ राजस्थान के प्रतापगढ जिले में स्थित श्री होरी हनुमानजी मंदिर के दर्शन किये और उन्हें शिवना नदी के क्षेत्र में पर्याप्त वर्षाकर नपा के जलस्त्रोतों को भरने के लिये श्री होरी हनुमानजी को धन्यवाद दिया। यह उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों शिवना नदी के उपरी क्षेत्रों में हुई वर्षा के कारण नपा का कालाभाटा बांध लगभग 169 फीट तथा कथार बांध लबालब भर गया है तथा नपा के रामघाट में भी पानी संग्रहित हुआ है। हर वर्ष नपा के जलस्त्रोतों में पानी संग्रहित होने व शिवना का प्रवाह होने पर नपा के जलकार्य समिति के पदाधिकारीगण व कर्मचारीगण प्रतिवर्ष श्री होरी हनुमानजी के दर्शन करते है और उन्हें धन्यवाद देते है। इस वर्ष भी शिवना में प्रवाह प्रारंभ होने व जलस्त्रोतों में पानी की पर्याप्त आवक होने पर नपाध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, नपा जलकार्य समिति सभापति श्री निलेश जैन ने होरी हनुमानजी के दर्शन किये। इस अवसर पर नपा जलकार्य समिति सदस्य एवं पार्षदगण श्रीमती सुनीता भावसार, श्रीमती सुनीता नंदलाल गुजरिया, कमलेश सिसौदिया, गोवर्धन कुमावत, माया भावसार, पार्षद प्रतिनिधि राकेश भावसार, नंदलाल गुजरिया ने भी श्री होरी हनुमानजी के दर्शन किये।

कन्या महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह का शुभारम्भ

मंदसौर, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। शासकीय कन्या महाविद्यालय, मंदसौर के प्राचार्य डा.सुधीर रायजादा ने बताया कि, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में 01 जुलाई 2025 से तीन दिवसीय दीक्षारंभ समारोह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के प्रथम दिवस की अध्यक्षता करते हुए रासेयो प्रभारी डा.राजश्री ठाकुर, समाजशास्त्र विभाग द्वारा महाविद्यालय में होने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम में छात्राओं को अपनी जिज्ञासाओं को सामने रखने का अवसर दिया गया। छात्राओं की जिज्ञासाओं का समाधान डॉ.निरंजन गंगवाल द्वारा किया गया। स्पोर्टस की जानकारी क्रीडा अधिकारी द्वारा दी गई। कार्यक्रम का संयोजन डा.अंजली जैन द्वारा किया गया एवं आभार श्री मनीष पांचाल, क्रीडा अधिकारी ने माना।

सीईओ एवं एडीएम ने जनसुनवाई में 139 आवेदकों की सुनी समस्याएं

नीमच, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव एवं एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में जनसुनवाई करते हुए 139 आवेदकों की सुनी समस्याएं और उनका निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

इस अवसर एसडीएम श्री संजीव साहू, संयुक्त कलेक्टर श्री राजेश शाह, डॉ.ममता खेंडे, सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे। जनसुनवाई में चेनपुरा के भारतसिह, चंद्रपुरा की ताराबाई, चडौली की भागवतीबाई, लेवडा की शांतिबाई, मनासा के दिनेश, टी.आई.टी.कॉलोनी नीमच के मनीष, खोर के रवि, रामप्रसाद, बाबुलाल, सोनियाना के शंभुलाल, हनुमंतिया के मोहन लाल, श्रीपुरा के देवीलाल, खोर की भंवरी बाई, जावी के शांतिलाल, साल्याखेडी के आजाद सिह, कुण्डखेडा के रमेश, बोरखेडी के भवरलाल नायक, भरभड्या के नंदकिशोर एवं ग्रामीण, नलखेडा के जगदीश आदि ने अपनी समस्याओं से संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए। इसी तरह दौलतपुरा के मुरलीधर, रामपुरा के गोपी, कुचदौड की शांतिबाई, आलोरी गरवाडा के किशनलाल, जगेपुर मीणा के कन्है,यालाल, सादडी रोड बघाना के गुणवंत, साकरिया खेडी के सीताराम, चेनुपरा खदान के दशरथ, पडदा के घीसालाल, भाटखेडा के बगदीराम कुमावत, चपलाना के मोहन लाल, बरखेडा जाट की गंगाबाई ने भी अपनी समस्याओं से संबंधी आवेदन जनसुनवाई में प्रस्तुत किए, जिस पर जिला पंचायत सीईओ ने कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

भारतीय लोकतंत्र पर प्रहार था आपातकाल...

मंदसौर, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। 25 जून का दिन प्रतिवर्ष हमे स्मरण कराता हे भारतीय राजनीतिक इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय की जब पूरे भारत में संविधान को ताक में रखकर इस देश की तत्कालीन सरकार ने आपातकाल लगा दिया था। आपातकाल यानि इमरजेंसी। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक पूरे 21 माह तक सम्पूर्ण भारत एक प्रधानमंत्री की जिद और अहंकार की भेंट चढकर रह गया था। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई सरकार का लोकतांत्रिक विरोधी व्यवहार नही हो सकता। यह भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद पर सबसे गहरी चोट थी। इस दौरान नागरीको के अधिकार और स्वतंत्रता का घोर हनन किया गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादित और अलोकतांत्रिक काल था। वास्तव में आज की पीढी इस बात की कल्पना भी नही कर सकती की उन 21 महीनो में पूरे भारत में कैसी खामोशी, श्मशान जैसा सन्नाटा, अत्यधिक निराशा और अज्ञात भय में जी रहे राष्ट्रभक्तों को किस मानसिक प्रताडना से गुजरना पडा था। इस आंदोलन में सहभाग करने वाले मिसाबंदियो के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार हुए उनके विषय में चर्चा करते समय रोंगटे खडे हो जाते हे। आपातकाल के दौर में निष्पक्ष पत्रकारिता की भी खूब परीक्षा ली गई। आज के पत्रकारो के लिए भी आपातकाल किसी सबक से कम नही हे। अधिकांश मीडिया संस्थान के झुक जाने के बावजूद जनता की आवाज नही दब पाई और आज भी उन पत्रकारो और मीडिया समूह को सम्मान के साथ याद किया जाता हे जिन्होने सत्ता से भयभीत होकर घुटने टेकने के स्थान पर सत्ता के अहंकार से टकराने का सामर्थ्य व साहस दिखाया। पत्रकारिता का स्वरूप हर दौर के लिए एक सबक के साथ ही मिसाल के तोर पर भी याद किया जाता हे। लोकतंत्र की मजबूती का मीडिया की स्वतंत्रता से सीधा संबंध हे। यही कारण हे की जब भी जन्हा भी लोकतंत्र को कमजोर करने या उसकी हत्या का प्रयास किया गया पहला वार मीडिया की स्वतंत्रता पर किया गया। आपातकाल की घोषणा के साथ ही विपक्षी दल के नेताओ को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानो पर जेल में बंद कर दिया गया। इस दौरान ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत गिरफ्तार हुए व्यक्ति को अदालत में पेश करने और जमानत मांगने का अधिकार नही था। जेल में बंद नेताओ को किसी से मिलने की अनुमति नही थी। उनकी गिरफ्तारी की सूचना परिवार और रिश्तेदारो को भी नही दी जाती थी। पूरे देश में जबरदस्ती लोगो की नसबंदी करवाई गई। काफी अधिक आलोचनाओं के बाद इस थोपे गए आपातकाल को 1977 में रद्द कर दिया गया और अदालत ने इस आपातकाल की घोषणा को अनुचित कृत्य का दर्जा दिया। आपातकाल के बाद ही देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। यह किसी एक दल की सरकार नही थी बल्कि जनता के द्वारा हि समर्थित उस विपक्ष की सरकार थी जिसका दमन करने के लिए ही आपातकाल को हथियार बनाया था। रामधारी सिंह दिनकर की कविता की यह पंक्तियां आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन में जनता की ताकत बन गई थी की सिंहासन खाली करो की जनता आती हे। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता हे की साधारण व्यक्तियों ने अपने मताधिकार से यह सिद्ध कर दिया की वे समय आने पर ऐतिहासिक व क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हे।

गौरव सोनी, मंदसौर

पत्र संपादक के नाम

संपादक की सहमति आवश्यक नहीं

क्या मंदसौर न्याय दिला पायेगा अपनी बेटी को..?

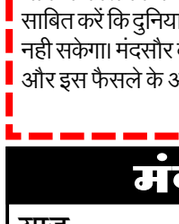

मंदसौर, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। मन्दसौर में एक बेटी के साथ वहशी हरकत करने वालो की फाँसी को ताउम्र जेल में बदल दिया गया। इस सिस्टम में फिर कोई किरदार आये और अच्छे आचार व्यवहार के नाम पर वहशी दरिंदो को फिर खुले आसमान के निचे दरिंदगी करने के लिए छोड दिया जाएगा। तो कोई नही बात नही होगी। सोशल मीडिया दो दिन गरियाने लगेगा। मीडिया जगाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन मशीनी हो चुका समाज जो कोर्ट क्या किसी भी फैसले को बदलवाने की ताकत रखता है। वो ही अफीमी नशे में हो तो कोई क्या करेगा ?

दरिदों की मदद करने वाले कौन लोग है ?–पैसा खर्च किसने किया ? यह सब नाक के नीचे होता रहा और मंदसौर सोता रहा ? क्या न्यायालय परिसर में ऐसा कोई व्यक्ति नही था जिसको इसकी जानकारी नही थी ? क्या यह फैसला रातो रात यह फैसला हो गया ? जवाब नही ही है।लेकिन में अब दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह जो दरिदों की ये केवल सज़ा कम करवाने का फैसला भर नही उन्हें फिर से जेल से बाहर लाने की और का पहला कदम है। हम आज कुछ नही करेंगे और यूँ ही सोते रहेंगे तो कुछ समय बाद कुछ बिकेंगे कुछ मैनेज होंगे और ये दरिंदे देखते ही देखते आज़ाद होंगे। ये खबर पढ कर खून में उबाल आयेगा। फिर दिन ढलने के साथ ठंडा हो जाएगा।

जनता की अदालत और जनता के आगे सुप्रीम कोर्ट को भी कई बार झुकना पडा है। फैसले बदलने पडे है। अदालत के फैसले में बेकसूर हो चुके जेसिका लाल के हत्यारों को फिर से सज़ा देनी पडी। अब सवाल यह कि क्या मंदसौर ये कर पायेगा। किदवंती के अनुसार हम उस वीर यशोधर्मन की भूमि से है जो अपनी बहन के वचन के लिए खूंखार हूणों को परास्त कर अजर अमर हो जाये। क्या उस अबोध बेटी जिसको हमने दुखद घटना के समय मंदसौर की बेटी मान कर संघर्ष का शंखनाद किया था। उस जुनून उस खून में आये उबाल के कारण आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच पाए थे। जिनको फाँसी पर लटका देखना चाहते थे। वो सरकारी रोटी पर पलेंगे। और फिर न जाने कब अच्छे व्यवहार बर्ताव के कारण बाहर आजाये पता नही। फिर किस बेटी की अस्मिता पर हाथ डालेंगे पता नही ? और हां अगर वो जीवन भर जेल में भी रहे तब भी मन्दसौर तो हारा हुआ कि कहलायेगा। एक बात और ये फैसला दूसरे दरिंदों के हौसलें बढाने वाला है। इसलिए हमें यह लडाई इसलिए नही छेडनी की किसी को फांसी क्यों नही दी गई। मन्दसौर को यह लडाई इसलिए लडनी पडेगी क्यों कि दरिंदों के आंखों में ख़ौफ़ होना चाहिए।फांसी इसलिए भी ताकि दूसरा कोई ये हिमाक़त नही कर सके। इस लडाई को मंदसौर को लडना ही पडेगा उसके लिए जिसको बेटी कहा.. हाँ उस बेटी के लिए जिसको दरिंदों ने नोच डाला। उस बेटी के लिए जिसकी तरह आपके हमारे घर मे भी कोई बेटी है उनके भविष्य केलिये। मन्दसौर ऐसी लडाई लडे की इसिहास रच दे।आइये हम साबित करें कि दुनिया की कोई ताकत लग जाये दरिंदो को फांसी के फंदे से बचा नही सकेगा। मंदसौर की बेटी का कोई पिता भाई बहन माँ सब सडक पर आएंगे और इस फैसले के अमल तक चुप नही बैठेंगे।

हितेश शुक्ला, मंदसौर

मंदसौर मंडी भाव

उपज	आवक बोरी में	न्यूनतम	अधिकतम
मक्का	75	2076	2340
उडद	10	3560	5000
सोयाबीन	7766	3100	4262
गैहु	8988	2350	2715
चना	515	4800	5401
मसुर	202	5950	6441
धनिया	206	5153	7085
लहसुन	14000	2900	8501
मैथी	724	3351	5252
मुंगफली	1346	3850	5300
अलसी	1680	6600	7166
सरसो	383	6201	6610
तारामीरा	9	5181	5242
इसबगोल	60	7600	10700
प्याज	4627	200	1050
कलोंजी	35	9800	20600
तुलसी बीज	9	9000	13900
डॉलर	18	5600	7600
तिल्ली	391	6800	9000
जौ	0000	0000	0000
मटरसुखी	2	2121	3201
असालीया	63	6441	6875
चियाबीज	90	10500	15300

एक बगिया मां के नाम परियोजना 15 अगस्त से होगी शुरू-मुख्यमंत्री

❊ प्रधानमंत्री श्री मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से मिली प्रेरणा ❊ मनरेगा से 30 हजार से अधिक महिलाओं की निजी भूमि पर लगेंगे 30 लाख फलदार पौधे ❊ 1000 करोड़ रुपए की राशि की जाएगी खर्च ❊ महिलाओं और स्व-सहायता समूहों की तरक्की का आधार बनेगी परियोजना

मंदसौर, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वसहायता समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए पूरे देश में ज्ञान अभियान चलाया जा रहा है। पीएम श्री मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर प्रदेश में भी नई परियोजना शुरू की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर स्वसहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़ी घोषणा की है। प्रदेश में मनरेगा के माध्यम से एक बगिया माँ केनाम परियोजना चलाई जाएगी। परियोजना के अंतर्गत मनरेगा के माध्यम से प्रदेश की 30 हजार से अधिक स्व सहायता समूह की पात्र महिलाओं की निजी भूमि पर 30 लाख से अधिक फलदार पौधे लगाएं जाएंगे जो महिलाओं की आर्थिक तरक्की का आधार बनेंगे।

30 हजार एकड़ निजी भूमि पर किया जाएगा पौधारोपण-प्रदेश की स्व-सहायता समूह की 30 हजार से अधिक महिलाओं की 30 हजार एकड़ निजी भूमि पर एकबगिया माँकेनाम परियोजना के अंतर्गत पौधरोपण किया जाएगा। लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से आजीविका संवर्द्धन के लिए 30 लाख उद्यानिकी पौधों का रोपण कर फलोद्यान का विकास किया जाएगा।परियोजना के तहत हितग्राहियों को पौधे, खाद, गड्ढे खोदने के साथ ही पौधों की सुरक्षा के लिए कटीले तार की फेंसिंग और सिंचाई के लिए 50 हजार लीटर का जल कुंड बनाने के लिए राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही उद्यान के विकास के लिए महिला हितग्राहियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा।

15 अगस्त से शुरू होगा अभियान-एक बगिया माँ के नाम परियोजना अंतर्गत फलदार पौधारोपण का कार्य प्रदेश में 15 अगस्त से अभियान के रूप में शुरू होगा जो 15 सितंबर तक चलेगा।

फलदार पौधरोपण की इच्छुक महिलाओं का होगा चयन-एक बगिया माँ के नाम परियोजना के अंतर्गत आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूह की ऐसी महिला सदस्य, जो फलदार पौधारोपण करने हेतु इच्छुक हों, का चयन किया जाएगा। चयनित महिला हितग्राही के नाम पर भूमि नहीं होने की दशा में उस महिला के पति-पिता-ससुर-पुत्र की भूमि पर उनकी सहमति के आधार पर पौधरोपण किया जाएगा।

अत्याधुनिक तकनीक से किया जाएगा स्थल चयन-एक बगिया माँ के नाम परियोजना अंतर्गत पौधरोपण के लिए स्थल का चयन अत्याधुनिक तकनीक (सिपरी सॉफ्टवेयर) के माध्यम से किया जाएगा। स्थल चयन के लिए सिपरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से चयनित हितग्राही की भूमि का परीक्षण किया जाएगा। साथ ही तकनीक के माध्यम से जलवायु, कौन सा फलदार पौधा जमीन के लिए उपयुक्त है, पौधा किस समय और कब लगाया जाएगा इसका भी सिपरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से पता लगाया जाएगा। उपयोगी जमीन नहीं पाए जाने पर पौधरोपण का कार्य नहीं होगा।

ऑनलाइन ठगी : नए-नए तरीके से बनाया जा रहा लोगों को शिकार

मंदसौर, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। ऑनलाइन धोखेबाज लगातार लोगो को शिकार बना रहे हैं। शासन-प्रशासन द्वारा जागरुकता को लेकर चलाए जा रहे अभियानों के बाद भी कुछ ही दिनों में करीब 15 लाख की ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। नीत नए तरीके से ऑनलाइन ठगी का शिकार लोगों को बनाया जा रहा है। कभी एजेंसी दिलाने के नाम पर तो कभी शादी के नाम पर लोगों को ठगने का काम जारी है।

पुलिस विभाग द्वारा ठगी से बचने के लिए समय-समय पर अभियान चलाया जाता है। लेकिन, इस अभियान में अंचल में कितना काम किया गया। वह ठगी के आ रहे मामले बता रहे है। केवल स्कूलों में जाकर ही जागरुक किया जा रहा है। बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के माध्यम से भी जागरुक किया जाना चाहिए। ताकि आमजन तक यह बात पहुंचे और उनको पता चले कि किस तरह ठगी से बचा जा सकता है।

ठगी के कई मामले सामने आए है। इनमें सभी में एफआईआर तो हो गई। लेकिन बड़ी संख्या में इस तरह के मामलों में पुलिस का सफलता हाथ नहीं लगी है। केवल जांच तक ही मामला सीमित रह गया है। कुछ मामले तो पुलिस और साइबर सेल के बीच में घूम रहे है। अब तक उन पर विचार भी नहीं किया गया है। ठगी के मामलों को देखो तो दिन पर दिन इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन, उस अनुसार मामलों का खुलासा पुलिस नहीं कर पा रही है।

अब साल में तीन बार होंगी सीए फाइनल की परीक्षा, चार साल में पूरा होगा कोर्स

भोपाल, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे (Chartered Accountant Day 2025) (1 जुलाई) के अवसर पर सीए विद्यार्थियों और प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) सिलेबस को नया स्वरूप दिया गया है, जो अब विद्यार्थियों के लिए अधिक सुगम, व्यवस्थित और परिणामकारक साबित हो सकता है।

अब सीए कोर्स चार साल में पूरा किया जा सकेगा, जबकि पहले इसमें 5-6 साल तक का समय लग जाता था। साथ ही अब फाइनल परीक्षा साल में तीन बार होगी, जिससे परीक्षार्थियों को ज्यादा अवसर मिलेंगे। यह बदलाव 2025 सत्र से लागू होंगे।

क्या-क्या हुआ बदलाव में बदलाव?- 1. कोर्स के केवल तीन स्तर होंगे - फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। 2. इंटर और फाइनल दोनों में आठ की बजाय 6 पेपर होंगे (प्रत्येक ग्रुप में तीन)। 3. फाइनल लेवल में केस स्टडी आधारित नया पेपर जोड़ा गया है। 4. कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ को एक विषय में मिलाया गया है। 5. इंटर्नशिप (आर्टिकलशिप) की अवधि 3 साल से घटाकर 2 साल कर दी गई है। 6. ओपन बुक परीक्षा हटाकर केस स्टडी आधारित मूल्यांकन किया जाएगा। 7. नैतिकता, कॉरपोरेट गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जैसे समसामयिक विषयों को जोड़ा गया है। 8. स्टाइपेंड राशि में भी बढ़ोतरी की गई है।

अब आसान होगी तैयारी, सेल्फ स्टडी पर जोर-आईसीएआई भोपाल ब्रांच (ICAI - The Institute of Chartered Accountants of India) के चेयरमैन अर्पित राय के अनुसार, पहले तीन साल की ट्रेनिंग और लंबा कोर्स विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण होता था, जिससे लगभग 50% विद्यार्थी बीच में ही ड्रॉप हो जाते थे। लेकिन अब कोर्स को अधिक व्यावहारिक, स्मार्ट और इंडस्ट्री अनुरूप बना दिया गया है। विद्यार्थी अब फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की परीक्षा हर 3 महीने में दे सकेंगे, जिससे किसी कारणवश एक परीक्षा न दे पाने पर उन्हें लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

अब 4 साल में कैसे बनेगा सीए-
❊ पहला साल: फाउंडेशन + इंटर ❊ दूसरा व तीसरा साल: सीए के अधीन ट्रेनिंग (2 वर्ष) ❊ चौथा साल: फाइनल परीक्षा ❊ प्रैक्टिस की इच्छा रखने वालों के लिए एक साल की अतिरिक्त ट्रेनिंग

मध्यप्रदेश में सिर्फ 15% सफलता दर- मध्यप्रदेश में वर्तमान में लगभग 22,000 छात्र सीए कोर्स के विभिन्न चरणों में हैं, जबकि लगभग 12,500 सक्रिय सीए प्रोफेशनल्स हैं। हर साल करीब 800 विद्यार्थी सीए परीक्षा पास करते हैं, जो मात्र 15% सफलता दर को दर्शाता है।

पंचायत उप निर्वाचन 2025 के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

मंदसौर, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा पंचायत उप निर्वाचन 2025 के दृष्टिगत जिले की संबंधित गाम पंचायत/वार्ड के क्षेत्र की राजस्व सीमाओं में (जहां निर्वाचन होना है) कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्वाचन अवधि के दौरान प्रचार-प्रसार जोर-जोर से होने, सार्वजनिक सभाओं, ध्वनि विस्तार यंत्रों, घातक आग्नेय शस्त्रों के सार्वजनिक प्रदर्शन तथा उपयोग एवं लोक शांति कायम रखने, आमजन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

मंदसौर जिले की संबंधित ग्राम पंचायत/वार्ड के क्षेत्र की राजस्व सीमाओं में (जहां निर्वाचन होना है) कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्रों (फायर आर्म्स), घातक अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमशीर या अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार जिनसे जनसाधरण को चोट पहुच सकती है या जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकेगा, चाहे वह व्यक्ति लायसेंसधारी क्यों न हो। कोई भी व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय या समूह संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी से 24 घंटे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी भी स्थान पर आमसभा, धरना, रैली, प्रदर्शन एवं बन्द न तो आयोजित करेगा और ना ही इसके लिए प्रचार-प्रसार करेगा, ऐसी आमसभा, धरना रैली या बंद में विस्फोटक पदार्थ लेकर उपस्थित नहीं होगा। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/रिटर्निंग आफिसर अपने क्षेत्राधिकार में ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा प्रचार-प्रसार हेतु वाहन की अनुमति प्रदाय करेंगे। यह आदेश पंचायत उप निर्वाचन 2025 के कर्तव्य के लिए तैनात समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/पुलिस/विशेष पुलिस अधिकारी (सीआईएसएफ), बी.एस.एफ या सुरक्षा बल, जिन्हे जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्वाचन कर्तव्य के लिए तैनात किया जावे, उन पर लागू नहीं होगा। फेसबुक, व्हाटसअप, ट्विटर इत्यादि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कोई भी आपत्तिजनक/धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने वाली पोस्ट नहीं की जावें। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के कार्यवाही की जाएगी।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रहेगा प्रतिबंध

मंदसौर, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। पंचायत उप निर्वाचन 2025 अवधि के दौरान कोलाहल पर नियंत्रण बनाए रखना लोकहित में आवश्यक है, इस संबंध में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अदिती गर्ग ने जिले की संबंधित ग्राम पंचायत/वार्ड के क्षेत्र की राजस्व सीमाओं (जहां निर्वाचन होना है) में निर्वाचन सम्पन्न होने तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। निर्वाचन अवधि के दौरान ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन प्रचार के समय ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने के लिए विधिवत अनुमति संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी से लेना होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णित रिट पिटिशन (सिविल) क्रमांक 72/98 में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में पारित आदेश दिनांक 18 जुलाई 2005 का पालन सुनिश्चित किया जाना होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक की अवधि के लिए ही अनुमति प्रदान की जाएगी। अनुमति जारीकर्ता अधिकारी दिशा-निर्देशों के अधीन परिस्थितियों के अनुसार अनुमति देने या आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए सक्षम होंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड्स्पीकर/डी.जे./सम्बोधन प्रणाली) के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण/कार्यवाही के संबंध में म.प्र. शासन, गृह (सी-अनुभाग) विभाग, मंत्रालय भोपाल के 13 दिसम्बर 2023 द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर, एडीएम एवं सीईओ ने जनसुनवाई के दौरान 84 मामलों में सुनवाई की

मंदसौर, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन द्वारा सुशासन भवन सभाकक्ष में 84 आवेदकों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्दी निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मंदसौर जिले के नापाखेड़ा निवासी आवेदक विष्णु बाई ने पट्टे की जमीन पर कब्जा रोकने के संबंध में आवेदन दिया। जिस पर तहसीलदार मल्हारगढ को निर्देश दिए कि जांच कर कार्यवाही करें। मंदसौर जिले के आक्यापालरा के कैलाश मोगिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास के संबंध में आवेदन दिया। जिस पर सीईओ मल्हारगढ को निर्देश दिए कि जांच कर कार्यवाही करें। मंदसौर जिले के थडोद निवासी पेपाबाई ने भूमि पर कब्जे के संबंध में आवेदन दिया। जिस पर तहसीलदार मल्हारगढ को निर्देश दिए कि जांच कर कार्यवाही करें। मंदसौर जिले के गलियारा निवासी पार्वतीबाई ने आर्थिक सहायता राशी के संबंध में आवेदन दिया। जिस पर जनपद पंचायत सीतामऊ को निर्देश दिए कि जांच कर कार्यवाही करें। मंदसौर जिले के कुंडला निवासी आवेदक जोरावरसिंह ने कृषि भूमि के सीमांकन के संबंध में आवेदन दिया। जिस पर तहसीलदार सीतामऊ को निर्देश दिए कि जांच कर कार्यवाही करे। इसके साथ ही जनसुनवाई के दौरान न्यायालय आदेश का पालन करवाने, जमीन का हक दिलवाने, आर्थिक सहायता प्रदान करने, आवास योजना का लाभ प्राप्त करने, समग्र आईडी पर राशन प्राप्त करने, हेंडपम्प के संबंध में, वेतन राशि स्विकृत कराने व शासकीय भूमि का रास्ता खुलवाने इत्यादि तरह-तरह के आवेदन आये।

ग्राम पंचायत/वार्ड जहां निर्वाचन होना है वे शस्त्र लायसेंसधारी अपने शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराऐं

मंदसौर, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा ओदश जारी किया गया है, कि जिले में जहां संबंधित ग्राम पंचायत/वार्ड के क्षेत्र जहां निर्वाचन होना है। वह सभी लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस 29 जुलाई 2025 तक (पंचायत उप निर्वाचन 2025 की समाप्ति तक) के लिए तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिए है। लायसेंस में दर्ज शस्त्र सम्बंधित पुलिस थानों में तत्काल जमा कराना अनिर्वाय होगा। धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) (ख) के अंतर्गत मंदसौर जिले के संबंधित ग्राम पंचायत/वार्ड के क्षेत्र जहां निर्वाचन होना है। शस्त्र लाईसेंस अस्थाई रूप से निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि तक के लिए निलंबित करते हुए मंदसौर जिले में (संबंधित ग्राम पंचायत/वार्ड के क्षेत्र जहां निर्वाचन होना है) तत्काल प्रभाव से समस्त प्रकार के घातक हथियार व आग्नेय शस्त्रों के प्रदर्शन व उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित करते हुए। सभी शस्त्र लाईसेंसधारी (संबंधित क्षेत्र जहां निर्वाचन होना) अपने शस्त्र लाईसेंस पर स्वीकृत/दर्ज शस्त्र संबंधित थाने में जमा करायें। यह आदेश पंचायत उप निर्वाचन 2025 के कर्तव्य के लिए तैनात समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/पुलिस/विशेष पुलिस अधिकारी (सी.आई.एस.एफ), बीएसएफ या सुरक्षा बलों, नगर सैनिक बल जिन्हे जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्वाचन कर्तव्य के लिए नियुक्त किया गया है, उन पर लागु नही होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मंदसौर राजस्व जिले में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों में तथा औद्योगिक संस्थानों, कोषालय की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल आदि पर यदि आग्नेय शस्त्र हो तो उन पर भी आदेश लागू नहीं होगा। इसके साथ ही कर्तव्यस्थ लोकसेवक/पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान शस्त्र धारण कर सकेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

शहर कांग्रेस द्वारा आज ज्ञापन दिया जाएगा

मंदसौर, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मन्दसौर अध्यक्ष डॉ राघवेंद्रसिंह तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री जीतू जी पटवारी के विरुद्ध असत्य आधारों एवं झूठे तथ्यों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में अशोकनगर जिले के मुंगावली पुलिस थाने पर झूठी ऋखठ दर्ज करने पर प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला कांग्रेस के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री विपिन जी जैन के मार्गदर्शन में शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मन्दसौर द्वारा दिनांक 02 जुलाई 2025 बुधवार को मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन पुलिस अधीक्षक मंदसौर को दिया जाएगा। सभी कांग्रेसजन 11 बजे जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी चौराहा मन्दसौर पर एकत्रित होकर वाहनों से पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाएंगे जहां पर 11.30 बजे ज्ञापन दिया जाएगा एवं झूठी ऋखठ वापस लेने की मांग की जाएगी। डॉ तोमर ने सभी वरिष्ठ नेतागण, प्रदेश,जिला,ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारीगण, मंडलम,सेक्टर अध्यक्षगण, पार्षद,पूर्व पार्षद गण,सभी मोर्चा,विभाग,प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण,सभी कांग्रेस कार्यकर्तागण से अपील की है कि वह सभी समय पर गांधी चौराहा 11 बजे पहुंचकर अपनी भागीदारी करें।

मृत्यु के बाद किसी को जीवन का उपहार देना सिर्फ दान नहीं, अमरता है-मुख्यमंत्री

भोपाल, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देहदान या अंगदान करने वालों के परिजन को राज्य सरकार 26 जनवरी एवं 15 अगस्त के कार्यक्रमों में सम्मानित करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर कहा कि मृत्यु के बाद किसी को जीवन का उपहार देना सिर्फ दान नहीं, बल्कि यह अमरत्व प्रदान करने जैसा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि देहदान अथवा हृदय, लीवर व गुर्दा दान (डोनेट) करने वाले देहदानियों/अंगदानियों के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी।

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से 13 बच्चों का हुआ नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण

मंदसौर, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। डीपीओ श्री बीएल बिश्नोई द्वारा बताया गया कि, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के माध्यम से अनुयोग हॉस्पिटल मंदसौर में जांच शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में सभी बच्चों की सभी आवश्यक जांचें नि:शुल्क की गई। बच्चों को सुपोषण किट भी अनुयोग हॉस्पिटल की ओर से नि:शुल्क प्रदाय किया गया। कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने बच्चों से भेंट कर उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा की जानकारी ली।सुपोषण किट में मल्टीविटामिन, कैल्शियम,और प्रोटीन पाउडर दवाएं शामिल थी। नि:शुल्क जांचें:जनरल हेल्थ चेक उप,आंखों की जांच ,दांतों की जांच,एलर्जी की जांच और अन्य जांचे जो बच्चे के लिए जरूरी थी। पीएम केयर्स योजना योजना उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता या अभिभावक को खो दिया है। इस योजना का उद्देश्य इन बच्चों की व्यापक देखभाल करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

महाराणा प्रताप राइफल शूटिंग क्लब मंदसौर ने मप्र में फहराया परचम

मंदसौर, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। बडे ही हर्ष का विषय है इंदौर में स्थित बीएसएफ रेवती रेंज पर 10 मीटर राइफल शूटिंग एवं 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में महाराणा प्रताप राइफल शूंटिंग क्लब मंदसौर के शूटर ने भाग लिया जिसमें दो शूटर का प्री नेशनल हेतु चयन हुआ है जिसमें राजवर्धन सिंह राठौड ने 400 में से 368 अंक एवं ऐराफ मेव ने 400 में से 376 अंक बनाकर मंदसौर जिले का नाम गौरवान्वित किया इस पर मंदसौर जिले के माननीय सांसद महोदय सुधीर गुप्ता, माननीय विधायक महोदय विपिन जैन तथा कोच कृति भाटी एवं तरुण प्रताप सिंह सोलंकी ने उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए शूटर को शुभकामनाए दीं

पुष्पांजली/उठावना

श्री अवधेश कुमार दीक्षित (विधिक सेवा प्राधिकरण मन्दसौर) के पूज्य पिता जी उत्कर्ष,मलय एवं कीर्ति के दादा जी श्री विशम्भर दयाल जी दीक्षित का 90 वर्ष की आयु में सोमवार 30 जून को निधन हो गया है। उनकी आत्मा की शांति के लिए पुष्पांजली का आयोजन उनके निवास जी 1 शिक्षक नगर ऑफिसर कॉलोनी महू नीमच रोड साई मंदिर के सामने मंदसौर पर दिनांक 02 जुलाई बुधवार प्रात: 10 बजे है।

❊❊❊ शोकाकुल ❊❊❊
दीक्षित परिवार मंदसौर

श्री धाकड़ महासभा युवा संघ की जिला कार्यकारिणी की घोषणा

पपोंडिया एवं धाकड़ जिला मीडिया प्रभारी मनोनीत

नगरी, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। श्री धाकड महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र नागर एवं युवा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन धाकड के निर्देशानुसार तथा प्रदेश अध्यक्ष रामविलास धाकड की सहमति से श्री धाकड महासभा युवा संघ के जिला अध्यक्ष रामेश्वर धाकड नगरी ने संघ की जम्बो जिला कार्यकारिणी की घोषणा मंगलवार को की। श्री धाकड महासभा युवा संघ की जिला कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष भोलेशंकर पंडोपा (हिंगोरिया), सह कोषाध्यक्ष कपिल पपोंडिया(धमनार), जिला विधि न्याय विभाग मुकेश पेपिया (गोपालपुरा) एवं विशाल धाकड (रलायती) कार्यालय मंत्री कमलाशंकर मदारिया (मंदसौर),जिला मिडिया प्रभारी लक्ष्मीनारायण (पिंटू) पपोंडिया नगरी एवं बबलू धाकड (धुंधडका) मनोनीत किए गए। साथ ही कार्यकारिणी में जिला महामंत्री पद पर सोहन पपोंडिया धमनार, अर्जुन धाकड पिपलिया, किशोर नायमा बड़वन, कपिल हकवाडिया नाहरगढ एवं उदयलाल धाकड खेरखेडी तथा जिला उपाध्यक्ष पद पर दिनेश हकवाडिया ऐरा, कृष्ण गोपाल खडावदा, प्रहलाद नरवादिया रलायती, नंदकिशोर मेहता धुंधडका, चेतन धाकड फतेहगढ, दिनेश वीर लदुसा तथा दुर्गालाल गरगामा लसुडी को मनोनीत किया गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर राधेश्याम बग्गड हिंगोरिया बड़ा, ईश्वर लाल धाकड धमनार, महेश धनोरा बनी, कारूलाल वाकतरिया बनी, सुरेश गरगामा मऊखेडी, चंद्रशेखर अटोलिया नगरी मोहनलाल धाकड सिखेडी बनाए गए। सोशल मीडिया प्रभारी लोकेंद्र सालित्रा लदूसा, संजय अटोलिया नगरी,अंकित ठन्ना फतेहगढ, समरथ सालित्रा बड़वन, विकास पपोंडिया धमनार, बाबूलाल खंबोरिया खेड़ा एवं जीवन धाकड ऐरा इसी प्रकार जिला प्रवक्ता पद पर प्रदीप ठन्ना फतेहगढ,अनिल बग्गड नगरी, उत्सव धाकड नाहरगढ एवं हरीश पपोंडिया लदूसा मनोनीत किए गए। इसके साथ ही सात पदों पर जिला प्रचार मंत्री एवं 82 सदस्यी जिला कार्यकारिणी की भी घोषणा की गई।

मप्र जन अभियान परिषद की समीक्षा बैठक सम्पन्न, लगाया एक पेड़ मां के नाम

सीतामऊ, 01 जुलाई गुरु एक्सप्रेस। पोधारोपण के साथ ही बडेवृक्षों को काटने पर रोकथाम की सामाजिक चेतना जब तक आमजन मे नही आएगी, तब तक मुख्यमंत्रीजी का एक पेड मां के नाम अभियान सफल नही होगा। इस अभियान को सफल करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है।

मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता को 15 पौधे लगाने के साथ ही उन्हें बड़ा करने का संकल्प लेना है। 1 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न करना है। यह बात मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद की जिला समन्यवयक तृप्ती वैरागी ने जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर भडकेश्वर महादेव मंदिर पर सीतामऊकी समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद की नवांकुर संस्थाएं,ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों के साथ ही मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 30 मार्च से 30 जून तक अलग-अलग स्थानो पर जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जल स्त्रोतों की साफ सफाई कर जल संरक्षण के लिए जल दुत ने अहम भूमिका निभाई है। जिला समन्वयक तृप्ती वैरागी ने कहा कि पोधारोपण कर एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल करने के लिए प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरण मित्र को लगना होगा। साथ ही जनअभियान परिषद के कार्यकर्ता पौधारोपण कर एमपीजेएपी पोर्टल पर गतिविधी अपलोड करेंगे। इस अवसर पर विकासखंड समन्वयक नारायणसिंह निनामा ने कहा कि विकासखंड की सभी नवांकुर संस्थाएं एवं परामर्शदाता ,ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के सदस्य पर्यावरण को लेकर सजग रहे,ओर अधिक से अधिक पोधारोपण करें।कार्यक्रम मे नवांकुर संस्थाओं के प्रतिनिधी पंकज काला, संगीता काला,हरिओम गंधर्व, दिलीप भटनागर, रजनीश शर्मा, परामर्शदाता हेमंत गौड, चरण सिंहचौहान के साथ ही धानडाखेडा पंचायत के सरपंच, सहायक सचिव ओंकारलाल, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के कैलाश गुर्जर, कचनारा के भगतराम राठौर के साथ ही मुख्यमंत्री समुदायिकता नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के विद्यार्थी मुकेश चौहान, सत्यनारायण दास एवं समस्त सामाजिक कार्यकर्ता विशेष रूप से उपस्थित थे। बैठक के पूर्व सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भडकेश्वर महादेव पर चंबल नदी किनारे श्रमदान कर जल स्त्रोतो की साफ सफाई की। सभी के द्वारा एक पेड मां के नाम लगाया गया और उसका संरक्षण करने की शपथ ली गई। जल गंगा संवर्धन अभियान मे जल दुत को प्रमाण पत्र भी विपरीत किये गये।संचालन पंकज काला ने किया। अंत मे आभार दिलीप भटनागर ने माना। यह जानकारी परामर्शदाता हरिओम गंधर्व ने दी।

स्वत्वाधिकारी, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक आशुतोष नवाल के लिए गुरु मीडिया एण्ड इंटरटेनमेन्ट कम्पनी, शक्ति नगर मन्दसौर से मुद्रित एवं 77 लक्ष्मीनगर, वेदान्त विहार मन्दसौर से प्रकाशित। (हर प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र मन्दसौर रहेगा) संपादक- आशुतोष नवाल RNI-MPHIN2006/20356
समाचार पत्र में छपे विज्ञापनों के लिए समाचार पत्र उत्तरादायी नहीं है एवं विज्ञापनो में प्रकाशित विचार विज्ञापनदाता की निजी राय है। इससे समाचार पत्र का कोई संबंध नहीं है। फोन 313880, मो. 9425105927,28 ashugurumds@gmail.com, ashu_guru2@yahoo.co.in